● वर्ष-3
● अंक-125
रायपुर, बुधवार 03 जनवरी 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› बच्चे के फोन एडिक्ट होने की वजह ...

लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम

नई दिल्ली। देश में लोकसभा चुनाव से पहले %नागरिकता संशोधन अधिनियम% (सीएए) के नियम लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार के विश्वस्त सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में होमवर्क पूरा कर लिया है। संभव है कि जनवरी या फरवरी में सीएए के नियम लागू हो जाएंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों के तहत भारत के तीन मुस्लिम पड़ोसी देश, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं, से आए गैर मुस्लिम प्रवासी लोगों के लिए भारत की नागरिकता लेने के नियम आसान हो जाएंगे। इन छह समुदायों में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। एक दिन बाद ही इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी। सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी। ऐसे अल्पसंख्यक, 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हों। इससे पहले भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 11 साल तक भारत में रहना जरूरी था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत इस नियम को आसान बनाया गया है। नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 से 6 साल किया गया है।

यह कानून, अभी तक इसलिए लागू नहीं हो सका, क्योंकि सीएए के तहत नियम बनाए जाने बाकी हैं। राज्यसभा और लोकसभा में अधीनस्थ विधान पर संसदीय समितियों ने क्रमश: 31 दिसंबर, 2022 और 9 जनवरी, 2023 तक केंद्रीय गृह मंत्रालय को विस्तार दिया था। इसके बाद दोबारा से संसदीय समितियों ने विस्तार को मंजूरी दी थी।

सीएए को लेकर देश में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं। कई राजनीतिक दलों ने भी इसका विरोध किया था। उस वक्त केंद्र सरकार इसे लागू करने का मन बना चुकी थी, लेकिन कोरोना के चलते सीएए अधर में लटक गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 200 से अधिक जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। इन सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यह कहते रहे कि सीएए हर सूरत में लागू किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण इस अधिनियम को लागू करने में देरी हुई है। जो लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा, वे गलत साबित होंगे (ह्लोंगे)। किसी व्यक्ति की खुद नागरिकता नहीं देता है। इसके जरिए पात्र व्यक्ति, आवेदन करने के योग्य बनता है। यह कानून उन लोगों पर लागू होगा, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे।

रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह

बाबर जन्म स्थान से आएगा जल

■ 156 देशों के जल से होगा रामलला का जलाभिषेक

लखनऊ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में रामलला का अभिषेक 156 देशों के जल से होगा। खास बात यह है कि इस जल में मुगल शासक बाबर के जन्मस्थान उज्बेकिस्तान का भी जल शामिल है। इसके अलावा चीन, पाकिस्तान, दुबई समेत महाद्वीप अंटार्कटिका के भी जल से रामलला का अभिषेक होगा। यह दावा दिल्ली के पूर्व विधायक डॉ विजय जौली का है।

उन्होंने अमर उजाला को बताया कि जल से भरा एक बड़ा कलश विहिप के संरक्षक मंडल सदस्य दिनेश चंद्र को उन्होंने दिसंबर माह में ही सौंप दिया है। दिनेश चंद्र ने वादा किया है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रामलला के अभिषेक के लिए इस जल का उपयोग किया जाएगा। डॉ. विजय जौली के अनुसार दुनिया के 170 देशों में दिल्ली स्टडी ग्रुप के संबंध हैं। वह कई वर्षों तक भाजपा के विदेश विभाग के प्रमुख रहे। दिल्ली स्टडी ग्रुप की भी जल संग्रह अभियान में अहम भूमिका रही। कई देशों की सरकारें हमारे संस्था के सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में बुलाती रहती हैं, इसका फायदा भी हमें मिला।

पिछले साल 23 अप्रैल को हमारी संस्था की ओर से अयोध्या में जलाभिषेक

कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में 13 देशों के राजदूत और 40 देशों के 200 लोगों का समूह अयोध्या पहुंचा था। इस कार्यक्रम में 156 देशों से एकत्रित जल को रामलला की चौखट पर अर्पित किया गया था। इस कार्यक्रम से पहले हमने सभी देशों का थोड़ा-थोड़ा जल तांबे के एक बड़े कलश में एकत्र कर सुरक्षित रख लिया था। जिसे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रामलला के अभिषेक की मंशा से विहिप को सौंप दिया गया है।

डॉ. जौली ने बताया कि जल संग्रह में सर्वधर्म के लोगों का सहयोग है। सऊदी अरब से हिंदुओं ने जल भेजा। कजाकिस्तान से मुस्लिम ताज मोहम्मद ने अपने यहां की प्रमुख नदी का जल भेजा। ईरान की एक मुस्लिम महिला ने जल भेजा। कीनिया से सरदारों की मदद से जल संग्रह हुआ। सिंधियों ने खतरा मोल लेकर पाकिस्तान से जल भेजा था।

औवेसी पर भारत को तोड़ने का आरोप

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम युवाओं से केंद्र द्वारा की जा रही गतिविधियों से सावधान रहने की अपील की और कहा था कि देश भर में मस्जिदें आबाद रहनी चाहिए, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसको लेकर भाजपा के फायर फ्रेंड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि औवेसी भारत को तोड़ना चाहते हैं, युवाओं को भड़का रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में भगवान राम का डीएनए है। हम सब उनकी संतान हैं। भाजपा नेता ने कहा कि 1000 वर्षों तक सनातन धर्म और हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया। ये समय हिंदुओं के पुनर्जागरण का है। असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद के संदर्भ में कहा कि वह स्थान जहां पिछले 500 वर्षों से पवित्र कुरान का पाठ किया गया था, वह अब उनके हाथ में नहीं है। ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि हैदराबाद के सांसद वही कर रहे हैं जो वह सबसे अच्छा करते हैं - 'राम मंदिर के अभिषेक को सांप्रदायिक बनाना'।

भगवान का बुलावा आएगा तो जरूर जाएंगे: अखिलेश

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने को लेकर कहा कि भगवान का बुलावा आएगा तो जरूर जाएंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह भगवान का अनुष्ठान है। सीएम भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। भगवान राम ने जिन्हें बुलाया है वे अवश्य (अयोध्या) जाएंगे। उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधते हुए कहा, कोई नहीं जानता कि भगवान कब किसे बुलाएंगे और ये लोग (भाजपा नेता) भगवान के इतने करीब हैं कि उन्हें तारीख पता है। योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री ये बातें कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि बीजेपी नेता लिस्ट बना रहे हैं कि कौन मेहमान होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। ये भगवान श्री राम का कार्यक्रम है। इन लोगों (बीजेपी) को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसे बुलाएंगे वह जाएगा। इस बीच, आयोजकों ने नए साल के दिन पूजा किए गए 'अक्षत' हल्दी और घी के साथ मिश्रित चावल के दानों का वितरण शुरू किया।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज शाम यहां छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरविंद अवस्थी और प्रदेश संयोजक श्री राजेश मिश्रा ने मुख्यमंत्री को बधाई दी और उन्हें रामचरित मानस की प्रति भेंट की।

सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल, सील वजूखाने की सफाई की मांग उठाई

उत्तर प्रदेश। वाराणसी की एक अदालत ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की अनुमति दी थी। याचिका में दावा किया गया है कि वहां शिवलिंग मौजूद है जो हिंदुओं के लिए पवित्र है। शिवलिंग के आस पास गंदगी न हो इसके लिए उचित व्यवस्था की जाए। ये भी दावा किया है कि मौके पर बहुत दिन से साफ सफाई नहीं की गई है। पानी की

टंकी में मछलियां मर गई है। इसकी वजह से दुर्गंध आ रही है। वाराणसी जिला अदालत ने गुरुवार को तीन आवेदनों पर सुनवाई की अगली तारीख 3 जनवरी तय की थी। जिसमें अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी (एआईएमसी) का एक आवेदन भी शामिल है, जिसमें यह आदेश देने की मांग की गई है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर एक रिपोर्ट को सीलबंद रखा जाए। कवर और किसी भी पक्ष को तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि हलफनामे पर यह निजी वचन न दिया जाए कि इसे किसी को लीक नहीं किया जाएगा।

ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली एआईएमसी ने यह आवेदन दायर किया था जबकि दूसरा आवेदन चार हिंदू महिला वादी के वकील विष्णु शंकर जैन ने 18 दिसंबर को दायर किया था।

प्रमुख समाचार

शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है सरकार-राहुल गांधी

नई दिल्ली। सड़क दुर्घटना पर भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों को लेकर ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। इसको लेकर उन्होंने एक एक्स पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। उन्होंने आगे कहा कि जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे, तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं।

सरकार पर वार करते हुए राहुल ने कहा कि सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्ठी में झोंकना उनकी जीविका को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। और साथ ही, इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ 'वसूली तंत्र' को बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने हमला जारी रखते हुए कहा कि लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार 'शहंशाह के फरमान' और 'न्याय' के बीच का फर्क भूल चुकी है। आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता ने ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता का स्थान ले लिया है।

'अबकी बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार', भाजपा ने तैयार किया नया नारा

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा

अपनी तैयारी में जुटी हुई है। इसको लेकर भाजपा ने अपना नया नारा भी तैयार कर लिया है। इस बार के चुनाव में भाजपा 'अबकी बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार' का नारा देगी। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक भाजपा ने राज्य, लोकसभा और विधानसभा स्तर पर संयोजक और सहसंयोजक भी तय कर लिए हैं। भाजपा इस बार के चुनाव में महिला वोटर और युवाओं पर फोकस करेगी। ऐसे मतदाताओं को भी साधने की कोशिश में रहेगी जो की पहली बार वोट डालने जाएंगे। बीजेपी सोशल मीडिया अभियान में भी तेजी लाएगी। खबर यह भी है कि जल्दी पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होगा। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अलग-अलग समय पर देश के अलग-अलग हिस्सों का दौरा करेंगे।

उत्तर प्रदेश स्कूल वैन में अब सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य

उत्तरप्रदेश। 29 दिसंबर को राज्य सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी स्कूली वाहनों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य कर दिए गए हैं। परिवहन प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरलू द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह प्रावधान राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के तीन महीने बाद लागू होगा। हालाँकि कुछ वैन में उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमों के अनुसार पहले से ही निगरानी कैमरे लगाए गए थे, नई अधिसूचना में स्कूल वैन के लिए कैमरे लगाने की समय सीमा तय की गई है। प्रस्तावित केंद्रीकृत वाहन स्थान ट्रैकिंग केंद्र कार्य करने के लिए तैयार होने के बाद सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे। परिवहन विभाग ने राज्य में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (वीएलटीएस) के कार्यान्वयन के लिए पहले ही एक निजी एजेंसी नियुक्त कर दी है। एजेंसी को ढांचे के तहत वाहनों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म को तैनात करने, एकीकृत करने, परीक्षण करने और संचालित करने का अधिकार है। यह परियोजना दोपहिया, तिपहिया और ई-रिक्शा को छोड़कर सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरणों से जोड़ने का प्रयास करती है।

बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, जाति आधारित सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक हों

बिहार। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य द्वारा किए गए जाति-आधारित सर्वेक्षण की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए सवाल उठाया कि सरकार किस हद तक सर्वेक्षण डेटा के

ऊपर रोक लगा सकती है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ वर्तमान में बिहार सरकार के फैसले को बरकरार रखने के लिए 2 अगस्त को दिए गए पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ गैर-सरकारी संगठनों यूथ फॉर इक्वेलिटी और एक सोच एक प्रयास और अन्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। जाति आधारित सर्वेक्षण करना। विशेष रूप से अदालत ने पक्षों को विस्तार से सुनने से पहले जाति सर्वेक्षण डेटा को प्रकाशित करने या उस पर कार्रवाई करने से राज्य को रोकने के लिए स्थगन या यथास्थिति का कोई भी आदेश पारित करने से लगातार इनकार कर दिया है। पीठ ने आज पक्षों के वकील से कहा कि कानूनी मुद्दे, यानी उच्च न्यायालय के फैसले की सत्यता की जांच करनी होगी।

जम्मू-कश्मीर को लेकर अमित शाह की बड़ी बैठक

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जम्मू-कश्मीर के

एलजी मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, एनएसए अजीत डोभाल, आईबी के निदेशक तपन डेका और अन्य अधिकारी भाग ने भाग लिया। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में उन्होंने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जम्मू-कश्मीर में पूर्ण क्षेत्र प्रभुत्व और पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के बीच बेहतर समन्वय का निर्देश दिया। उन्होंने स्थानीय खुफिया जानकारी को बढ़ावा देने और मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में पिछले तीन साल से जम्मू-कश्मीर में लागू केंद्र सरकार के जीरो टेरर प्लान पर चर्चा हुई। मोदी सरकार का लक्ष्य 2026 तक 'जीरो टेरर' योजना को पूरी तरह से लागू करने का है। पिछले साल 21 दिसंबर को दोपहर करीब 3.45 बजे राजौरी के पुंछ क्षेत्र में डेरा की गली से गुजर रहे सेना के दो वाहनों पर आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी के बाद शुरू हुई मुठभेड़ में चार सैनिकों के मारे जाने और तीन के घायल होने के कुछ दिनों बाद यह बैठक आयोजित की गई थी।

180 दिन बाद बॉर्डर पार नहीं कर सकेगा पाकिस्तानी ड्रोन

नई दिल्ली। पाकिस्तान की तरफ से 'हथियार व ड्रग्स' को लेकर भारतीय सीमा में आने वाले ड्रोन का जल्द ही खेल खत्म होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने की तकनीक खोज निकाली है। तीन तरह के उपकरणों का ट्रायल चल रहा है। इनमें से एक या दो तकनीकों को बॉर्डर के हर हिस्से पर लगाया जाएगा। एंटी ड्रोन तकनीक को जमीन पर उतरने में महज 180 दिन लगेंगे। यानी छह माह पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन की एंट्री पूरी तरह से बंद हो जाएगी। पाकिस्तान के ड्रोन, भले ही कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हों, वे भारतीय सीमा में नहीं घुस पाएंगे। खास बात है कि इस तकनीक में बॉर्डर गार्ड फोर्स को गोली नहीं चलानी पड़ेगी। तकनीक सिस्टम, पाकिस्तान के ड्रोन को वहीं पर जाम कर देगा।

तीन तरह के ट्रायल पर चल रहा काम

केंद्रीय गृह मंत्रालय के विश्वस्त सूत्रों ने बताया, पाकिस्तान की तरफ से पंजाब व जम्मू कश्मीर सहित दूसरे सीमावर्ती क्षेत्रों में आने वाले ड्रोन को जाम करने के लिए, तकनीकी सिस्टम का ट्रायल, अंतिम चरण में हैं। तीन तरह के ट्रायल पर काम चल रहा है। ट्रायल के नतीजे उत्साहवर्धक हैं। खास बात है कि यह एंटी ड्रोन तकनीक, बॉर्डर के हर हिस्से पर लगाई जाएगी। पाकिस्तान ड्रोन की घुसपैठ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पंजाब और जम्मू कश्मीर से लगते बॉर्डर पर तीन मॉड्यूल के अंतर्गत ट्रायल शुरू हुआ था। ड्रोन को खत्म करने की जिस तकनीक पर काम हो रहा है, उसमें काफी हद तक सफलता मिल रही है। ट्रायल के फाइनल नतीजों का विश्लेषण करने के बाद एंटी ड्रोन तकनीक को देश के सभी बॉर्डर पर लगाया जाएगा। अगले छह माह के भीतर, पाकिस्तान से लगता बॉर्डर एंटी ड्रोन तकनीक से लैस होगा।

गिराए जा रहे हथियार, कारतूस और ड्रग्स के पैकेट

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी %आईएसआई% द्वारा पंजाब में लगातार ड्रोन भेजे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और राजस्थान में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। ड्रोन के जरिए हथियार, कारतूस और ड्रग्स के पैकेट गिराए जाते हैं। पिछले साल ही बीएसएफ ने लगभग 100 पाकिस्तानी ड्रोन को बॉर्डर पर मार गिराया था। पाकिस्तान से पंजाब में आए दिन ड्रोन के जरिए भेजे जा रहे ड्रग्स के पैकेट जब्त किए जा रहे हैं। ड्रग्स को लेकर पंजाब सरकार,

केंद्रीय गृह मंत्रालय की रणनीति के मुताबिक काम कर रहा है। पंजाब में बीएसएफ, एनसीबी और पुलिस, ये तीनों पूर्ण समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान से आने वाले ज्यादातर ड्रोन चीन निर्मित होते हैं।

चीन निर्मित ड्रोन की तकनीक में होता है बदलाव

ये ड्रोन, बीएसएफ की नजरों से बच जाएं, इसलिए इनकी तकनीक में कुछ बदलाव किया जाता है। कहीं पर ड्रोन की आवाज बंद कर दी जाती है, तो कुछ ड्रोन की सिग्नल लाइट को हटा दिया जाता है। पंजाब से लगते भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर सर्दियों में जब घना कोहरा छाया था, तब दर्जनों ड्रोन आए थे। उस वक्त ड्रोन की ऊंचाई ज्यादा रखी जाती थी। आवाज और ब्लिंकर को भी कंट्रोल कर देते थे। बीएसएफ ने पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में जो ड्रोन गिराए हैं, उनकी लंबाई छह फुट तक रही है। कुछ ड्रोन तो 25 हजार एमएच की बैटरी वाले भी मिले हैं। ऐसे ड्रोन की मदद से 20-25 किलोग्राम सामान कहीं पर पहुंचाया जा सकता है।

एडीएस लगे वाहनों की खरीदी

पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्विलांस के लिए बीएसएफ द्वारा %सीआईबीएमएस% का ट्रायल किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन का पता लगाने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम %एडीएस% लगे वाहनों की खरीद प्रक्रिया जारी है। इस सिस्टम की मदद से भारतीय सीमा में रात को या धुंध के दौरान आने वाले ड्रोन का भी पता लगाया जा सकता है। बीएसएफ के पास इजराइल निर्मित 21 %लॉन्ग रेंज रीकानिसंस एंड ऑब्जरवेशन सिस्टम% (लोरोस) हैं। इसके जरिए दिन में 12 किलोमीटर दूर से किसी मानव का पता लगाया जाता है। अब बीस किलोमीटर की रेंज वाले लोरोस या एचएचटीआई खरीदने की तैयारी चल रही है। बीएसएफ को बहुत जल्द 546 एचएचटीआई (अनकूल्ड) लॉन्ग रेंज वर्जन कैमरे मिल जाएंगे। इसके अलावा 878 एचएचटीआई कैमरे, जिनमें 842 (अनकूल्ड) और 36 (कूल्ड) कैमरे खरीदने की प्रक्रिया चल रही है।

3600 ड्रोन को कंट्रोल करने का फॉर्मूला

पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में पहले दो चार ड्रोन आते थे, अब पिछले कुछ समय से लगातार ड्रोन आ रहे हैं। कई बार तो एक ही दिन में कई ड्रोन छोड़े जा रहे हैं। बीएसएफ द्वारा मार गिराए गए अधिकांश ड्रोन, क्वैडकॉप्टर (मॉडल डीजेआई मेविक 3 क्लासिक, मेड इन चाइना) और क्वैडकॉप्टर (मॉडल डीजेआई मेट्रिस 300 आरटीके, मेड इन चाइना) सीरिज के होते हैं। हालांकि पाकिस्तान को अभी तक चीन से %3600% ड्रोन को एक साथ कंट्रोल करने का फॉर्मूला नहीं मिल सका है। पाकिस्तान से पंजाब में आने वाले अनेक ड्रोन पहले असेंबल भी किए जाते हैं। पाकिस्तान को चीन से सस्ती दरों पर ड्रोन के पुर्जे मिल जाते हैं। इन्हें पाकिस्तान में जोड़ कर ड्रोन तैयार किया जाता है।

नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध, बसें नहीं चलने से यात्री परेशान

बिलासपुर। नए मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के दूसरे दिन भी खासा असर देखने को मिला। यात्री बसों के साथ मालवाहक गाड़ियों और ऑटो चालक संघ ने अपनी गाड़ियां सड़कों पर नहीं उतारी। जिसकी वजह से यात्री परेशान होते रहे। वहीं पेट्रोल पंप में भी लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है।

नए मोटर व्हीकल एक्ट के संसोधन करने की मांग को लेकर सोमवार से ट्रक, ट्रॉली सहित सभी कमर्शियल वाहनों के पहिए थमे हुए हैं। ट्रक चालक और ट्रांसपोर्टर संगठन के बाद अब कमर्शियल वाहनों के चालक भी इस हड़ताल का समर्थन करते हुए सड़क पर उतर आए हैं। हड़ताल के दूसरे दिन यात्री बस से लेकर ऑटो- टैक्सी के भी पहिये थम हुए है। सभी ने अपनी गाड़ियों को स्टैंड में खड़ा कर दिया है। जिससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नए साल पर कई लोग अमरकंटक घूमने पहुंचे लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं चलने से वे यहां वहां भटक रहे हैं।

रामू, संभलपुर ने कहा अमरकंटक घूमने आए थे। यहां पहुंचे तो पता चला कि गाड़ी वालों की स्ट्राइक चल रही है। जहां से आए वहां कोई स्ट्राइक नहीं है। 20 लोग आए है। काफी परेशानी हो रही है। घर वापस लौटेंगे।

ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल में टैंकर चालकों के शामिल होने से पेट्रोल पंप में भी लोड नहीं पहुंच रहा है। जिससे पेंड्रा में कई पेट्रोल पंप में फ्यूल की शॉर्टेज हो गई है। पेट्रोल पंप में लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। कुछ पेट्रोल पंप पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं तो कुछ पेट्रोल पंप में लिमिटेड पेट्रोल होने के चलते लिमिट से पेट्रोल दिया जा रहा है।

पेट्रोल पंप संचालक ने कहा पब्लिक की भीड़ जमा हो रही है। सभी को पेट्रोल देने की कोशिश हो रही है। बाइक वालों को 200 रुपये का पेट्रोल दिया जा रहा है। कार वालों को 500 रुपये का पेट्रोल दिया जा रहा है। लंबी दूरी वालों को ज्यादा का भी दे रहे हैं। स्टॉक फिलहाल तो है। 1 जनवरी से हड़ताल करनी थी लेकिन टैंकर चालकों ने 2 दिन पहले ही हड़ताल कर दी। इस वजह से लोड नहीं आया।

सभी पेट्रोल पंपों में फिलहाल डीजल का पर्याप्त स्टॉक होना बताया जा रहा है। लेकिन शाम तक नया लोड नहीं आने से पंप में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिससे आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है।

चालकों की हड़ताल से पेट्रोल की सप्लाई प्रभावित

कोरबा। केंद्र सरकार द्वारा चालकों के खिलाफ लाए गए नए कानून को लेकर सभी चालक तीन दिन के हड़ताल पर चले गए हैं। जिसका व्यापाक प्रभाव कोरबा में देखने को मिल रहा है। टैंकर चालकों के हड़ताल पर चले जाने से पेट्रोल पंप में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति ठप्प हो गई है। जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरबा शहर के अधिकतर पेट्रोल पंप ड्राई हो गए है। जिससे लोगों की भारी भीड़ पेट्रोल पंपो पर देखने को मिल रही है।

भारी वाहन चालकों के तीन दिवसीय हड़ताल का काफी बुरा प्रभाव कोरबा जिले में देखने को मिल रहा है। टैंकर चालकों के हड़ताल पर चले जाने से पेट्रोल पंपो में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति ठप्प हो गई है। पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई नहीं हो पाने के कारण जिले के अधिकतर पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं जिससे लोगों को पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा है।

हालांकि, कुछ पेट्रोल पंपो में पेट्रोल डीजल जरुर मिल रहा था। जहां लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। शहर के लगभग सभी पेट्रोल पंपो में इसी तरह का दृश्य देखने को मिला। लोगों ने बताया कि पेट्रोल डीजल नहीं मिलने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कोरबा की तरह प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इसी तरह की स्थिती निर्मित हो गई है। पेट्रोल-डीजल नहीं मिल पाने के कारण हाहाकार मच गई है। चालकों की हड़ताल तीन दिन तक चलेगी। तीन दिन के बाद भी हड़ताल समाप्त नहीं हुई तो समस्या काफी बढ़ जाएगी। कोरबा शहर के टीपी नगर, शारदा विहार, बुधवार बाईपास पेट्रोल पंप, इसके अलावा कोई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पेट्रोल खत्म हो गया है। लोग वापस लौट रहे हैं। कोरबा के निहारिका घंटाघर, कोसाबाड़ी पेट्रोल पंप, कुमार पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में हड़ताल का दूसरा दिन कई पेट्रोल पंप ड्राई, सड़कों पर भटक रहे यात्री

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। वाहन चालकों के हड़ताल का आज दूसरे दिन भी खासा असर देखने को मिला है। यात्री बसों के साथ मालवाहक गाड़ियों और ऑटो चालक संघ आज दूसरे दिन भी अपने वाहनों को सड़कों पर नहीं उतारे। जिसकी वजह से यात्री परेशान होते रहे तो हड़ताल में पेट्रोल पंप के टैंकर चालकों के शामिल होने से पेट्रोल पंप में लोड नहीं पहुचने से पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है। जिसके कारण कुछ पेट्रोल पंप ड्राई है तो कुछ में लिमिटेड पेट्रोल होने के चलते लिमिट से इमरजेंसी कोटा से पेट्रोल दिया जा रहा है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के संसोधन के विरोध में जहां बीते दिन मोटर वाहन चालक ऑटो चालक सहित सभी कमर्शियल वाहनों के पहिए सोमवार से पूरी तरह से थम गए थे। ट्रक चालक ऑटो चालक एवं ट्रांसपोर्टर संगठन के बाद अब कमर्शियल सभी तरह के वाहनों के चालक इस हड़ताल का समर्थन करते हुए सड़क पर उतर आए हैं। जिसके चलते आज हड़ताल के दूसरे दिन भी यात्री बस से लेकर ऑटो-टैक्सी के भी पहिये थम हुए हैं। ये वाहन स्टैंड में खड़े कर दिए गए। वाहन चालकों के इस निर्णय से यात्रियों को खासी असुविधा का सामना करना पड़ा और लोग इधर उधर भटकते नजर आए। जिसके बाद अब पेट्रोल की समस्या से भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। हड़ताल में पेट्रोल टैंकर चालकों के शामिल होने के कारण पेट्रोल पंप में लोड नहीं पहुंचा और उसी के चलते पेट्रोल पंप में लोगों की लंबी-लंबी कतार देखने को मिली। वहीं आज सुबह से पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि, पेट्रोल पंप संचालकों की मानें तो कुछ पेट्रोल पंप पूरी तरह ड्राई हो चुके हैं तो कुछ में लिमिटेड पेट्रोल ही स्टॉक में है। जिसके चलते वे लिमिटेड पेट्रोल ही वाहनों को दे रहे हैं। हालांकि, सभी पेट्रोल पम्पों में डीजल का स्टॉक तो पर्याप्त है। लेकिन पेट्रोल नहीं होने से शाम तक लगभग सभी पेट्रोल पम्पों में पेट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जिसके चलते लोगों को एक बार फिर परेशान होना पड़ सकता है।

घर के बाहर टहल रही महिला को लगी गोली, डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर बचाई जान

कोंडागांव। जिले की यह पहली ऐसी घटना है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहां घर के बाहर टहल रही एक महिला के कंधे पर अचानक गोली लग गई और उसे पता भी नहीं चला। जब उनके कंधे में तेज दर्द हुआ तो उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके कंधे के अंदर फसी गोली को ऑपरेशन कर निकाला। वहीं इस मामले में पुलिस ने हवाई फायरिंग की आशंका जताई है।

कोंडागांव डीएनके वार्ड निवासी जिला अस्तपाल में नर्स के पद पर पदस्थ जयलक्ष्मी रक्षित पर आखिर गोली किसने चलाई, यह सवाल अब उठने लगा है। वहीं पुलिस सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। अस्पताल में पहले दिन महिला को प्राथमिक उपचार दिया गया। दूसरे दिन दर्द काफी बढ़ गया। जब दर्द कम नहीं हुआ तो एक्सरा किया तब उसके कंधे के अंदर गोली फसी हुई मिली, जिसे डॉक्टरों ने आपरेशन कर बाहर निकाला।

जब विधानसभा चुनाव के दौरान जिनको भी लाइसेंसशुदा हथियार दिए जाते हैं पुलिस उन्हें अपने पास जमा करवा लेती है। उसके बावजूद भी अगर किसी ने हवाई फायर किया है तो यह पुलिस पर भी सवाल उठ रहा है।

डॉक्टर एस नालगूलन ने कहा, हमने सफल आपरेशन कर लिया है। गोली बाहर निकाल ली है। महिला सुरिक्षत है। अगर गोली सिर के उपर लगती तो महिला की मौत भी हो सकती थी। फिलहाल महिला सुरिक्षत है। अगर गोली समय पर नहीं निकालते तो उसका जहर शरीर में फैल सकता था। अच्छा था समय पर पता चल गया और समय पर आपरेशन कर गोली निकाल ली गई।

मामले की जांच कर रही पुलिस : टीआई

थाना प्रभारी पहलाद यादव ने कहा, आज 2 जनवरी को प्रार्थी ने एफआईआर करवाई है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी पर हमला हुआ है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। आपरेशन के बाद बुलेट को हमने सुपर्द में ले लिया है और फारेंसिंक जांच के बाद ही पता चलेगा।

विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने लगाए जा रहे शिविर

स्वास्थ्य परीक्षण के साथ बनाया जा रहा आधार, आयुष्मान, जॉब कार्ड

कोरबा। प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के लोगों को लाभ दिलाने हेतु प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजाति के बसाहटों को चिन्हांकित कर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित एवं पात्र सभी हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। शिविर में शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा लोगों को विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग हेतु संचालित योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में जनजाति बहुल कोरबा जिले के ग्राम छातासराई, माखुरपानी, पतरापाली, गढ़उपरोड़ा, देवपहरी जैसे कई गांवों में शिविर का आयोजन किया गया।

गौरतलब है कि पीएम जनमन योजना का मूल उद्देश्य कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी), परिवारों और बस्तियों तक बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं को पहुंचाकर उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। पीएम जनमन योजना अंतर्गत कमजोर जनजाति समूहों के बसाहटों में विभिन्न विभागों के समन्वय से पेयजल, आवास, सड़क, आंगनबाड़ी के माध्यम से पोषण, आजीविका

संवर्धन हेतु कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा। शिविरों में विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के वंचित लोगों को आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, जनधन खाता, केसीसी, जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार पत्र, जॉब कार्ड सहित अन्य योजनाओं से लाभान्वित भी किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण के रूप में बीपी, शुगर, आंख, खून की जांच कर आवश्यक परामर्श एवं दवाइयां भी प्रदान की जा रही है। विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को शिविर तक लाने हेतु महिला कर्मचारियों, स्वसहायता समूह द्वारा सहयोग भी किया जा रहा है एवं शिविर की नियमित मॉनिटरिंग हेतु गठित जिला एवं ब्लॉक स्तरीय नोडल अधिकारियों की टीम द्वारा शिविर का निरीक्षण कर संबंधित विभागों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है।

दुर्ग के शिवनाथ नदी तट पर महाआरती का आयोजन

दुर्ग। हर साल की तरह इस बार भी नए साल के मौके पर शिवनाथ महोत्सव का आयोजन किया गया। दुर्ग में शिवनाथ नदी के तट पर बनारस की गंगा आरती की तरह ही महाआरती की गई। इस महाआरती को देने दुर्ग भिलाई समेत अन्य जिले से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शिवनाथ महोत्सव में अलग-अलग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।

शिवनाथ महोत्सव में एक तरफ जहां मंच के माध्यम से कलाकारों ने शिव जी के भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। वहीं शाम ढलते ही शिवनाथ नदी की तट पर 51 हजार दिए जलाए गए। दीपों की रोशनी से पूरा घाट जगमगा उठा। इसके बाद बनारस की गंगा आरती के तर्ज पर महाआरती की गई। इस महाआरती के लिए बनारस और हरिद्वार से 11 विशेषज्ञ पंडितों को बुलाया गया था। उनके द्वारा ये भव्य महाआरती आयोजित की गई। महाआरती को देखने के लिए प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे।

कार्यक्रम के आयोजक वरुण जोशी ने बताया कि शिवनाथ नदी को लीज मुक्त कराने और प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से यह पहली बार महाआरती का आयोजन किया गया था। पिछले 4 सालों से इस महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। इस महाआरती का मुख्य उद्देश्य दुर्ग की जीवनदायनी शिवनाथ नदी को बचाना है। कुछ समय पहले शिवनाथ नदी, जो कि विश्व की पहली नदी होगी, जिसे लीज पर दिया गया था।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

नक्सल मुठभेड़ में 6 महीने की बच्ची की मौत

बीजापुर। मुडवेंदी मुठभेड़ को लेकर नक्सलियों के पश्चिम डिवीजनल कमेटी के सचिव ने प्रेस नोट जारी किया है। जिसमें नक्सलियों ने जवानों पर सड़क का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर अंधाधुंध फायरिंग करने का आरोप लगाया है। इसी फायरिंग के दौरान मासूम बच्ची सोढ़ी बामन की मौत हो गई। साथ ही उसकी मां सोढ़ी मासे के घायल होने की बात कही गई है। प्रेस नोट में दो जवानों के घायल होने का दावा किया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने प्रेस नोट जारी करते हुए क्रॉस फायरिंग में मासूम बच्ची की मौत और उसकी मां के घायल होने की जानकारी दी गई थी। नक्सली नेता ने प्रेस नोट जारी कर इस कांड में शामिल जवानों को सजा देने की मांग की है। बता दें कि मुडवेंदी के जंगलों में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में एक 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई थी। वहीं इस मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवान भी घायल हुए थे।

धान बोनस के लिए मैनेजर ने मांगा कमीशन, सस्पेंड

बिलासपुर। जिला सहकारी बैंक के सीईओ ने बिलासपुर करगी रोड शाखा के बैंक मैनेजर को सस्पेंड कर दिया है। कलेक्टर के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है। शाखा के पर्यवेक्षक एवं प्रभारी शाखा प्रबंधक हरिश कुमार वर्मा के खिलाफ किसानों ने कमीशन मांगे जाने की शिकायत की थी। किसानों के मुताबिक कमीशन नहीं देने पर बोनस की राशि नहीं दी जा रही थी। साथ ही साथ मैनेजर किसानों से अभद्रता कर रहा था। करगीरोड सहकारी बैंक के मैनेजर ने किसानों को धान बोनस की राशि देने के लिए कमीशन की मांग की। जो किसान कमीशन नहीं दे रहा था उसे पैसा नहीं मिल रहा था। शाखा के पर्यवेक्षक एवं प्रभारी शाखा प्रबंधक के विरूद्ध किसानों ने कमीशन मांगे जाने और बोनस की राशि से कमीशन नहीं दिये जाने पर अभद्रता की शिकायत की थी।जिस पर बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्ट्या शिकायत सही पाई गई थी। जिसके बाद पर्यवेक्षक हरीश कुमार वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

श्रीराम की चरण पादुका का राजनांदगांव में भव्य स्वागत

राजनांदगांव। श्रीलंका के सीता माता मंदिर से भगवान श्रीराम की चरण पादुका अयोध्या ले जाई जा रही हैं। चरण पादुका की शोभायात्रा 15 दिसंबर श्रीलंका से शुरू हुई है, जो 22 जनवरी को अयोध्या में समाप्त होगी। यह शोभायात्रा आठ राज्यों से होती हुए अयोध्या पहुंचेगी। फिर, राम मंदिर में चरण पादुका स्थापित की जाएंगी। मंगलवार को यह शोभायात्रा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव पहुंची। गायत्री मंदिर से शुरू होकर पूरे शहर में शोभायात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रीराम भक्त मौजूद रहे। जय श्रीराम के जयकारे के पूरे शहर गूंज उठा। राजनांदगांव में राम भक्तों ने शोभायात्रा का भव्य स्वागत किया। गायत्री मंदिर से शुरू होकर पूरे शहर में शोभायात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रीराम भक्त मौजूद रहे। जय श्रीराम के जयकारे के पूरे शहर गूंज उठा। सदस्य यात्रा समिति के प्रदोष चव्हाणके ने बताया, %हमने राम राज्य युवा यात्रा निकाली है। यह शोभायात्रा 15 दिसंबर से शुरू हुई थी और 22 जनवरी को अयोध्या में समाप्त होगी।

कैफे में लगी भीषण आग लाखों का हुआ नुकसान

कांकेर। शहर के सेन चौक स्थित कैफे में अचानक भीषण आग लग गई। कैफे में लगी आग से पूरा कैफे जलकर राख हो गया। कैफे बंद होने के बाद कैफे में आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। नए साल के पहले दिन ही शहर में आगजनी की घटना सामने आई। बीती रात शहर के सेन चौक स्थित परिंदा कैफे में भीषण आग लग गई। जिसमे पूरा कैफे जलकर खाक हो गया है। परिंदा कैफे के संचालक अशोक उके ने बताया कि एक जनवरी की रात नौ बजे कैफे बंद कर घर चले गए थे। रात 10 बजे उन्हे कैफे में आग लगने की जानकारी मिली। कैफे जलने से तकरीबन 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। सेन चौक में संचालित परिंदा कैफे के संचालक अशोक ने बताया कि एक सप्ताह पहले ही कैफे शुरू किया था। रोज की तरह ही रात नौ बजे कैफे बंद कर घर चले गए थे। इसी बीच कैफे के पास मौजूद अन्य दुकानदारों ने कैफे में आग लगने की जानकारी दी। कैफे में रखे नगद दस हजार, नए फर्नीचर और अन्य सामान जल गया।

कांकेर में फर्जी पुलिस बनकर किया साइबर फ्रॉड

कांकेर। जिले के पुलिस ने सायबर फ्राड के नए तरीके का भांडा फोड़ किया है। कांकेर पुलिस ने 4 आरोपियों को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी फर्जी पुलिस बनकर सायबर अपराध को अंजाम देते थे। ऑनलाइन एफआईआर से नंबर निकाल कर आरोपी ठगी को अंजाम देते थे। आरोपियों ने कांकेर समेत छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में भी सायबर फ्रॉड को अंजाम दे चुके हैं। अन्य राज्यों में भी इस तरह के सायबर फ्राड को उन्होंने अंजाम दिया था। कांकेर एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया, कांकेर जिले के चारामा थाना में मनीषा वर्मा, पुष्पा बाई और उत्सव जुर्री ने शिकीयत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी पुलिस अधिकारी बनकर फोन करते थे और उनके प्रकरण में कार्रवाई और दूसरे पक्ष को जेल भेजने के नाम पर के नाम पर पैसों की मांग करते थे। शिकायत के आधार पर चारामा थाना पुलिस और साइबर सेल कांकेर की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम को आरोपी के खोजबीन के लिए मध्यप्रदेश रवाना किया गया। जहां टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

चिरमिरी ननि में करोड़ों का मंगल भवन अटका

■ **अफसरों पर आरोप**

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। चिरमिरी नगर निगम में किस तरह से पैसों की बर्बादी की जा रही है।इसकी एक बानगी मंगल भवन निर्माण कार्य में देखने को मिली है। एसईसीएल से मिली लीज की जमीन पर बिना एनओसी के ही निगम के अधिकारियों ने मंगल भवन बनाने की अनुमति दे दी। जिसका नतीजा ये हुआ कि आधे से ज्यादा जब ये मंगल भवन बनकर तैयार हो चुका था,तो उसमें रोक लगा दी गई। अब ये पूरा मामला संपदा न्यायालय के पास है।

आपको बता दें कि बिना एसईसीएल के परमिशन के 2 करोड़ 75 लाख की लागत से मंगल भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। नगर निगम चिरमिरी को एसईसीएल ने इसके लिए कई खत भी

लिखे।लेकिन आखिरकार जब कोई जवाब नहीं आया तो मामला संपदा न्यायालय कुरासिया में दर्ज करा दिया गया।जिसके बाद संपदा न्यायालय ने निगम के कार्य पर रोक लगा दी।जिसके बाद सोनामणि इलाके में बन रहा मंगल भवन का काम रोक दिया गया है।

इस मामले में जब तक संपदा न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता।तब तक मंगल भवन का काम पूरा नहीं होगा।लेकिन तब तक बिना किसी तैयारी और कागजी कार्रवाई के इतनी बड़ी राशि से मंगल भवन का बनना कई सवाल खड़े करता है।साथ ही एसईसीएल के क्षेत्र वाली जमीन पर जब तक प्रबंधन एनओसी ना दे तब तक किसी तरह का निर्माण नहीं होता है।ऐसे में यदि गलत जगह पर निर्माण हुआ,तो भविष्य में भवन जमीन में समा भी सकता है।इसलिए सुरक्षा कारणों से एसईसीएल क्षेत्र में निर्माण कार्यों में एनओसी जरूरी है।

एसईसीएल अधिकारी दिलीप गांगुली ने कहा एसईसीएल को जमीन वनविभाग से लीज पर मिली है।जिस पर किसी तरह का निर्माण नहीं हो सकता।बार-बार पत्र लिखने के बाद भी निगम ने ध्यान नहीं दिया।जिसकी वजह से न्यायालय की शरण में जाकर इस पर स्थगन लगाया गया है।

वहीं निगम चिरमिरी के नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह का कहना है कि अन्य संस्थान की जमीन पर निर्माण बिना एनओसी के नहीं किया जा सकता। इसलिए इस काम में जितनी राशि की बर्बादी की गई है वो अधिकारियों से वसूली जानी चाहिए।वहीं बीजेपी नेता की माने तो बार-बार पत्र लिखने के बाद भी एसईसीएल को कोई भी जवाब निगम की ओर से नहीं मिला।वहीं काम शुरु करा दिया गया।ऐसे में अब शासन को बड़ी क्षति होगी।ऐसे निगम के अफसरों को दंडित भी किया जाना चाहिए।

किसान बिंदेश्वर धान की बोनस राशि का उपयोग जरूरी काम को पूरा करने के लिए करेंगे

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को दो साल के धान खरीदी की बोनस राशि दे दी है। राज्य के किसान राशि पाकर खुश हैं और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद दे रहे हैं। किसान इस बोनस राशि का उपयोग नये घर बनाने, ट्रेक्टर का किस्त जमा करने, दैनिक उपयोग की सामान खरीदने में कर रहे हैं।

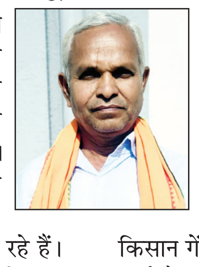

नारायणपुर जिले के कोचवाही निवासी किसान बिंदेश्वर नाग द्वारा दो वर्ष में 43 क्विंटल 20 किलो धान बेचने की बोनस राशि 12 हजार 960 रुपए बोनस राशि मिली है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब ट्रेक्टर का किस्त जमा में आसानी होगी। वहीं बाकुलवाही निवासी किसान योगेश्वर नाग ने 4 हजार 320 रुपए बोनस राशि मिलने पर इसे घर के उपयोग हेतु खर्च करने की बात कही और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है। कोचवाही निवासी 5 एकड़ कृषि भूमि के स्वामी बिंदेश्वर नाग ने दो वर्ष के धान विक्रय की बोनस राशि मिलने की खुशी प्रकट करते हुए बताया कि धान समर्थन मूल्य पर बेचा हूं, जिसकी राशि से खेत मरम्मत कराने में उपयोग करूंगा।

जिले के ग्राम केरलापाल के किसान सूबाय को 23 हजार 160 रूपये, दयावती को 14 हजार 760 रूपये, कुकड़ाझोर के किसान गेंदराम को 42 हजार 420 रूपये, कुम्हारपारा वार्ड के किसान श्यामचंद को 65 हजार 940 रूपये, खड़ीबहार के किसान धर्मराम को 3 हजार 480 रूपये, तेलसी के किसान हरून को 69 हजार 240 रूपये, देवांगनपारा के किसान विश्वनाथ को 52 हजार 920 रूपये, बाकुलवाकी के किसान समदूराम को 22 हजार 560 रूपये, बागडोंगरी के किसान अर्जुन को 9 हजार 480 रूपये, बिंजली के किसान बालसिंग को 21 हजार 600 रूपये, शंभूराम को 72 हजार 180 रूपये, बेलगांव के किसान नीलकंठ को 28 हजार 320 रूपये का बोनस मिला।

संक्षिप्त समाचार

कांग्रेस ने राज्य को कर्ज में डुबो दिया है : ओ पी चौधरी

रायपुर। पदभार संभालते ही वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने चारों तरफ माफिया राज फैला रखा था और छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से कर्ज में डुबो दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि जहां से आय हो सकती थी, कांग्रेस ने उन सबको पैसा कमाने का जरिया बना दिया। कांग्रेस ने स्टेट जीएसटी, एक्साइज, माइनिंग सभी जगह माफिया राज स्थापित कर दिया है। कांग्रेस ने आय को रोककर प्रदेश को दिवालियापन के कगार पर धकेलने का काम किया है। ओपी चौधरी ने आगे कहा कि सीएम विष्णु देव साय के नेतृत्व में हम वित्तीय हालत को ठीक करेंगे। साथ ही गुड गवर्नेंस स्थापित करके मोदी की सभी गारंटी को पूरा करेंगे।

ननकीराम कंवर ने संविदा में कार्यरत अधिकारियों के खिलाफ खोला मोर्चा

रायपुर। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय से संविदा में कार्यरत अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर इन अधिकारियों के जरिए चुनाव के दौरान सरकार में आने की कांग्रेस मंशा बताते हुए संविदा समाप्त करने की मांग की है। पूर्व विधायक ननकीराम कंवर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखे पत्र में कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव 2023 एवं लोकसभा चुनाव 2024 में फायदा लेने की मंशा से संविदा नियुक्ति दी गई थी। इन आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों में सामान्य प्रशासन सचिव डीडी सिंह, डीजीपी अशोक जुनेजा, डीजीपी जेल संजय पिल्ले, राजभवन आईएएस अमृत खलखो, आदिम जाति कल्याण विभाग एक अनंत शामिल हैं। इनके अलावा लघु वनोपज संघ राकेश चतुर्वेदी, वन औषधि पादप बोर्ड जेएस राव, नवाचार आयोग अध्यक्ष विवेक ढांड, धनंजय देवांगन, एसएस बजाज, राय सिंह ठाकुर, एसपीएस श्रीवास्तव, डीएम अवस्थी, संजय शुक्ला के अतिरिक्त और भी अधिकारी-कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति दी गई है। कंवर ने आरोप लगाया कि ये सभी अधिकारी एवं कर्मचारी कांग्रेस मानसिकता के है, जिन्हें नियम न होने के बाद भी संविदा नियुक्ति दी गई है।

विकास बन सकते हैं पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष

रायपुर। अब पांच साल सत्ता से बाहर रहना है ऐसे में विपक्ष की भूमिका भी तेज तर्रार ढंग से निभानी होगी,वर्तमान पीसीसी चीफ दीपक बैज उस स्वभाव के नहीं माने जाते हैं। हालांकि आदिवासी चेहरा व चुनाव से चार माह पहले ही जिम्मेदारी मिलने के कारण कुछ ज्यादा कर पाने का मौका नहीं मिल पाया शायद यहीं सोचकर आलाकमान ने हार के बाद भी उन्हे पद से नहीं हटाया लेकिन अब दो कार्यकारी अध्यक्ष उनके साथ जोड़ने की कवायद चल रही है। ताकि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में कुछ धार नजर आए और कार्यकर्ताओं में फिर से जोश भरा जा सके। इसके लिए विकास उपाध्याय व देवेन्द्र यादव का नाम सामने आया है लेकिन देवेन्द्र विधायक हैं इसलिए किसी और नाम पर विचार किया जा रहा है ताकि क्षेत्र के हिसाब से भी तालमेल बना रहे। यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई की भी सक्रियता चुनाव में नहीं रही है इसलिए पार्टी इन संगठनों के प्रमुखों को भी जल्द तलब करने जा रही है। कई जिलों के अध्यक्ष भी बदले जायेंगे।

इंटरलॉकिंग की वजह से दिल्ली, विशाखापट्टनम रूट पर चलने वाली ट्रेनों का रास्ता बदला

रायपुर। दिल्ली और विशाखापटनम रूट पर चलने वाली 8 ट्रेनों का रूट बदला गया है। सिकंदराबाद और विजयवाड़ा रेल मंडल में रेल लाइन विस्तार के इन ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, एक से 12 जनवरी तक नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य होगा, जिसकी वजह से 12 दिनों तक 8 ट्रेनें रायपुर और नागपुर होकर गुजरेगी। रूट में बदलाव की वजह से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के यात्रियों को आवाजाही में आसानी होगी। जिन ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया है, उनमें विशाखापटनम-नई दिल्ली एक्सप्रेस, नई दिल्ली-विशाखापटनम एक्सप्रेस, विशाखापटनम-गांधीधाम एक्सप्रेस, गांधीधाम-विशाखापटनम एक्सप्रेस, पुरीकुओखा एक्सप्रेस, ओखा-पुरी एक्सप्रेस, विशाखापटनम-निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस, निज़ामुद्दीन- विशाखापटनम एक्सप्रेस शामिल हैं।

मुख्यमंत्री को अभा कुशवाहा महासभा के पदाधिकारियों ने दी नववर्ष की शुभकामनाएं

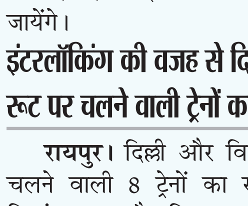

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राज्य अतिथि गृह पहुना में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ भेंटकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री संतोष मौर्य, उपाध्यक्ष श्री कमलेश सिंह, श्री संतोष कुशवाहा एवं पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे।

ड्राइवरों की हड़ताल से राजधानी में चरमराई व्यवस्था

नहीं चल पा रहीं गाड़ियां, पेट्रोल पंपों में वाहनों की लगी लंबी कतारें, सब्जियों की भी बढ़ी कीमत

रायपुर। देशभर में नए व्हिकल एक्ट को लेकर ड्राइवरों की हड़ताल जारी है। वाहन चालकों की हड़ताल से पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। पेट्रोल नहीं मिलने की अफवाह से शहरों के सभी पेट्रोल पंपों में लोगों की पेट्रोल-डीजल लेने के लिए लंबी कतारें लगी हैं। वहीं ट्रांसपोर्टिंग नहीं होने से सब्जियों की कीमत में उछाल आ गई है।

प्रदेश के सबसे बड़े थोक सब्जी बाज़ार में हड़ताल का असर दिखने लगा है। अलग-अलग जगहों से आने वाले सब्जियों का आवक कम या खत्म हो गया है। हड़ताल की वजह से सब्जियों के दाम तीगुने हो गए हैं। अन्य राज्यों से आने वाले वाहन भी मंडियों में नहीं पहुंच रहे हैं। थोक में हरी मिर्च के दाम 70 रुपए किलो हो गए हैं। थोक में धनिया 80 रुपए किलो, मटर 50 रुपए किलो, गोभी, करेला और सेमी के भी दाम बढ़ गए हैं। राजधानी रायपुर, बलौदाबाजार और अन्य शहरों के पेट्रोल पंपों में लोग डिब्बे में भी पेट्रोल ले जा रहे हैं, ताकि यदि हड़ताल लंबी चले तो उन्हें परेशानी न उठाना पड़े। लोगों के बीच चर्चा है कि हड़ताल लंबी चल सकती है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की किल्लत आ सकती है और सुविधा की दृष्टि से पेट्रोल डीजल की आवश्यकता इसलिए भीड़ लगी है। राजधानी रायपुर के डूमरतराई पेट्रोल पंप में भारी भीड़ लग गई है। रायपुर के कई पेट्रोल पंप में पेट्रोल खत्म हो गया है। ड्राइवरों की हड़ताल से आम जनता परेशान हो रहे हैं।

वहीं लंबी कतारों और पेट्रोल नहीं मिलने की अफवाह पर पेट्रोल पंप के मैनेजर शिवकमल मिश्रा ने बताया कि पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में है किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वाहन चालकों की हड़ताल की वजह से लंबी कतारें लगी है। हम सभी से उनकी आवश्यकता अनुरूप पेट्रोल डीजल दे रहे हैं।

खाद्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश

पेट्रोल-डीजल और घरेलू एलपीजी अतिआवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में शामिल है तथा इनकी आपूर्ति किसी भी स्थिति में किसी के द्वारा प्रभावित नहीं की जा सकती है। अतः इसकी सतत् परिवहन एवं आपूर्ति के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। राज्य में संचालित पेट्रोलियम / डीजल डिपो तथा एलपीजी डिपो में वाहनों के प्रवेश और निकासी में हडतालियों द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न किया जा सके। इसके लिए राजस्व पुलिस एवं खाद्य विभाग के अमले की ड्यूटी लगाई जाए।

पेट्रोल/डीजल डिपो तथा एलपीजी डिपो से वाहनों की रवानगी के उपरांत प्रदेश के किसी भी जिले में इनका परिवहन बाधित न किया जा सके। इसके लिए सभी टोल नाकों / चौकी में आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। आपके जिले में पदस्थ ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ जिले में पेट्रोल/डीजल/घरेलू एलपीजी की उपलब्धता तथा प्रदाय व्यवस्था की सतत् निगरानी के लिए जिला स्तरीय निगरानी दल का गठन कर इन आवश्यक वस्तुओं की सुगमता से उपलब्धता बनाई रखा जाए।

पेट्रोल डीजल खत्म, ट्रकों के पहिये थमे

शहर में पेट्रोल डीजल खत्म होने से हाहाकार मच गया है। लंबी कतार के बाद कहीं मिल रहे नहीं तो अधिकांश जगहों पर टैंक खाली हो चुकी हैं। हिट एंड रन मामले में कानून के नए प्रावधानों के विरोध में देशभर में ट्रक ड्राइवरों ने वाहन चलाने से इनकार कर दिया है। नतीजा, जगह-जगह भारी वाहन सड़कों पर खड़े हो गए हैं। इसके चलते पेट्रोल-डीजल, सब्जी जैसी अति आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर असर दिख रहा है। छत्तीसगढ़,एमपी, राजस्थान, समेत 10 राज्यों से पेट्रोल-डीजल पंप ड्राई होने की खबरें हैं। यहां लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। फल, सब्जी, दूध, कृषि के सामानों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। कई जगह प्रशासन ट्रांसपोर्टर्स से संपर्क कर आपूर्ति बहाल करवाने में लगा है।ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की आज दिल्ली में बैठक हो रही है. कुछ जगहों पर स्कूल बस व अन्य वाहन भी नहीं चल रहे हैं.वैसे प्रशासन पैनी नजर रखी हुई है लेकिन राजधानी समेत प्रदेश कई जगहों पर पेट्रोल डिजल की किल्लत से हाहाकार मच गया है।

कलेक्टर की जनता से अपील, कहा- जिले में पर्याप्त स्टॉक, अफवाहों से बचें

हिट एंड रन कानून में संशोधन के बाद नए नियमों को लेकर भारी वाहन चालक देशभर में चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे है। हड़ताल की वजह से वाहनों में पेट्रोल-डीजल भराने के लिए पंपों में लंबी कतारें लग रही है। हड़ताल से बनने वाली परिस्थितियों पर रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे सहित प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और स्थितियों की लगातार समीक्षा की जा रही है। ज़िले के पेट्रोल पंपों में अभी पर्याप्त स्टॉक आम जनों के उपयोग के लिए उपलब्ध है, लोगों को अफ़वाहों पर ध्यान ना देने और ज़रूरत के हिसाब से ही वाहनों में ईंधन भरवाने की अपील कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने राजधानी की जनता से की है। बता दें कि, ईंधन की निरंतर आपूर्ति के लिए ज़िला अधिकारी लगातार ऑयल वितरण कंपनियों से संपर्क में है और रायपुर ज़िले के सभी पेट्रोल पंपो में ऑयल कंपनियों द्वारा निरंतर डीज़ल-पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है। वितरण कंपनियों के प्रतिनिधियों ने आगे भी जनहित और जन उपयोग के लिए ईंधन की आपूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होने का आश्वासन प्रशासन को दिया है। कलेक्टर ने राजधानी की जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार पेनिक ना हो, किसी भी प्रकार के अपवाहों पर ना ध्यान दें और पेट्रोल-डीजल का अतिरिक्त स्टॉक ना रखें। जितनी आवश्यकता हो उतना ही लें पंपो में बेवजह भीड ना लगाए। अनावश्यक रूप से स्टॉक करने से पेट्रोल-डीजल की कमी हो सकती है। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कहा कि, इस संबंध में ऑयल कंपनियों से चर्चा की गई।

गणतंत्र दिवस पर कोविड गाइडलाइन जारी जरूरी हुआ मास्क पहनना, विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना तेजी से फैल रहा है। वहीं कोरोना से निपटने के लिए पाबंदियां भी बढ़ने लगी हैं। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को देखते हुए प्रदेशभर में कोविड गाइडलाइन लागू की गई है। इसमें में मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे आदेश जारी किए गए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन के लिए सभी विभाग, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर और समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पत्र लिखकर कोविड-19 महामारी को देखते हुए समारोह में विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। इसके साथ ही मास्क पहनना, सामाजिक दूरी जैसे नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह का आयोजन होगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन इस गरियामय समारोह में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इसके बाद उनका उद्बोधन होगा। इसके अलावा समारोह स्थल पर कई विभागों संस्थानों की ओर से चलित

झांकियों का प्रदर्शन होगा और पदक अलंकरण समारोह भी होगा। पिछले साल की तरह इस साल भी स्कूली बच्चों के कार्यक्रम और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। समारोह स्थल में रंगीन गुब्बारे भी उड़ाए जाएंगे। जिला मुख्यालयों में मंत्रीगण की ओर से ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली जाएगी और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि केवल जिला मुख्यालयों को छोड़कर अन्य किसी भी स्थान में परेड नहीं होगी। यहां के परेड में सेना, पुलिस, नगर सेना, जेल प्रहरी की टुकड़ियां भाग लेंगी। समारोह में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम गरिमामय और रूचिपूर्ण हों।

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद साय कैबिनेट की पहली बैठक आज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बुधवार को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की तीसरी अहम बैठक होगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद साय सरकार की ये पहली कैबिनेट बैठक है। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। इस बैठक में साय सरकार रामलला दर्शन योजना पर मुहर लगा सकती है।

इसके अलावा बैठक में राज्य सरकार प्रदेश में सीबीआई के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध भी हटा सकती है। राजिम पुन्नी मेले को फिर से अर्ध कुंभ का दर्जा देने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इससे पहले विष्णुदेव साय कैबिनेट की दो बैठकें हो चुकी हैं, हालांकि इन दोनों बैठकों में छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने

सीएम विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा ही शामिल हुए थे। पहली बार तीसरी कैबिनेट की बैठक में सीएम, दोनों डिप्टी सीएम और 9 मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में सीएम अपने मंत्रिमंडल से अफसरों का परिचय भी करा सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के समय अपने घोषणा पत्र को %छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी% के नाम से जारी किया था। अब तीन महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अपनी घोषणाओं और वादों को राज्य में तेजी से लागू करने के लिए साय कैबिनेट की बैठक अहम मानी जा रही है।

आईईडी ब्लास्ट में घायल जवानों से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा

जवानों का पूरा ख्याल रखने चिकित्सकों को दिये निर्देश

रायपुर। बीजापुर के गंगालूर इलाके में जवानों पर नक्सलियों द्वारा की गई फायरिंग के बाद घायल जवानों के उपचार की स्थिति जानने गृह मंत्री श्री विजय शर्मा अस्पताल पहुंचे। हॉस्पिटल में छत्तीसगढ़ पुलिस के 4 जवान श्री अरविंद एक्का, श्री कुंजाम जोगा, श्री रोशन हिकमी और श्री सुरेश कुमार मिच्छा तथा सीएएफ के 2 जवान श्री इंद्रजीत प्रसाद सिंह एवम मणिकांदन का ईलाज चल रहा है।

इस घटना में घायल 27 साल के जवान को अपना पैर खोना पड़ा है। एक जवान को गोली लगी है। भावुक परिवारजन भी अस्पताल में मौजूद थे। क्रासफायरिंग में मृत बच्ची की माँ का भी इलाज वहां चल रहा था। यह गृह मंत्री के लिए भी बहुत भावुक क्षण था। पीड़ित परिवारजनों के प्रति उन्होंने संवेदना जताई। गृह मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि ये हम सभी के लिए बहुत भावनात्मक क्षण है। हम सब आपकी

पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। जिस जवान की पत्नी अपने पति की पीड़ा देखकर चीत्कार रही थी उसे संबल बंधाते हुए गृह मंत्री ने कहा कि बहन यह पीड़ा हम सबकी है। हम अपने जवानों के साथ हर स्थिति में खड़े हैं।

वहां मौजूद अधिकारियों से गृह मंत्री ने कहा कि जो जवान अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए गश्त पर निकलते हैं। उन पर इस तरह कायराना हमला किया जा रहा है। यह बौखलाहट है। इस तरह की क्रूरता को बख्शा नहीं जाएगा। जिस जगह माओवादियों ने जवानों पर हमला करने का निर्णय लिया होगा, इस बात की आशंका भी होगी कि वहां पर मासूम ग्रामीण भी चपेट में आ सकते हैं। इस पर भी क्रूरतापूर्वक हमला किया गया। हम अपने जवानों के साथ हर स्थिति में खड़े हैं। उन्हें मजबूत करेंगे। उन्हें हर जरूरी संसाधन प्रदान करेंगे। गृह मंत्री जी के साथ आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहेब, डीजीपी श्री अशोक जुनेजा, पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, डॉ. सुनील खेमका एवं हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित थे।

प्रदेश में 31 दिसंबर तक 38.59 लाख टन धान की हुई खरीद

रायपुर। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अपने बफर स्टॉक के लिए तेजी से धान की खरीद कर रहा है। छत्तीसगढ़ की नई सरकार को धान किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,203 रुपये के मुकाबले प्रति क्विंटल 3,100 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। ऐसे में विशेषज्ञ का कहना है कि इससे राज्य में खरीद में कुछ सुधार हो सकता है। छत्तीसगढ़ में चावल की खरीद 31 दिसंबर तक 38.59 लाख टन बताई गई है, जो एक साल पहले के 51.61 लाख टन से 25 फीसदी कम है।

साल 2022 में अक्टूबर-दिसंबर के दौरान एफसीआई साल 2021-22 के मुकाबले 11 प्रतिशत अधिक धान की खरीदी की थी। नए आंकड़ों के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और अन्य उत्तरी राज्यों में धान की खरीद दिसंबर में पूरी हो गई, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह जनवरी के अंत तक जारी रहेगी। एफसीआई पंजाब में 125.08 लाख टन धान खरीदने में कामयाब रही है, जो एक साल पहले के 121.91 लाख टन से 2 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह हरियाणा में यह आंकड़ा साल 2022-23 में 39.51 लाख टन के मुकाबले 39.42 लाख टन है। इस वर्ष पंजाब में धान खरीद का लक्ष्य 122 लाख टन और हरियाणा में 40 लाख टन

निर्धारित किया गया था तेलंगाना में धान की खरीद 37.40 लाख टन से 28 प्रतिशत घटकर 27.11 लाख टन रह गई है।

एफसीआई ने इस साल चावल खरीद में समग्र गिरावट के लिए छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनावों को जिम्मेदार ठहराया है और उम्मीद जताई है कि इस पर पर्दा डाल दिया जाएगा। लेकिन पिछले एक पखवाड़े में, तेलंगाना में अंतर और बढ़ गया है जबकि छत्तीसगढ़ में कुछ सुधार देखा गया है। इसी तरह ओडिशा में धान की खरीद में कुछ सुधार देखा गया है, क्योंकि 15 दिसंबर तक खरीद 39 प्रतिशत कम थी, जबकि अब यह 26 प्रतिशत कम है। दूसरी ओर, आंध्र प्रदेश में अंतर 56 प्रतिशत से अधिक बना हुआ है। एफसीआई अब तक ओडिशा में 8.93 लाख टन और आंध्र प्रदेश में 5.07 लाख टन धान खरीद सका है।

मैं कार्रवाई करने के लिए नहीं व्यवस्था सुधारने आया हूं: स्वास्थ्य मंत्री

- **पदभार ग्रहण करते ही एक्शन मोड में आए श्याम बिहारी जायसवाल, डीकेएस अस्पताल का किया औचक निरीक्षण**

रायपुर। प्रदेश के नए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विभागीय कामकाज शुरू करने के बाद अस्पतालों का औचक निरीक्षण शुरू कर दिया है। मंत्री ने आज उन्होंने शास्त्री चौक में स्थित दाऊ कल्याण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीज़ और उनके परिजनों से रूबरू होकर उनका हाल जाना। इससे पहले सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री ने आंबेडकर अस्पताल पहुंचकर कर अस्पताल का दौरा किया था।

औचक निरीक्षण पर डीकेएस पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि, मैं कार्रवाई करने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था सुधारने के लिए आया हूं। हम प्रदेश की 3 करोड़ जनता को सरल सुलभ और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देने के संकल्प को लेकर काम कर रहे है। अगर किसी विशेषज्ञ की कमी है या कोई और कमी है तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है। इस पर लगातार फीडबैक ले रहे है। हमारी प्राथमिकता है कि प्रदेश के लोगों को इलाज के लिए बाहर जाना ना पड़े।

इससे पहले सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंत्रालय महानदी भवन में पदभार संभाला। इसके बाद उन्होंने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों

सहित विभागीय कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी। पिल्ले भी मौजूद थीं। उन्होंने अधिकारियों से राज्य के सभी जरूरतमंद लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के सभी शासकीय अस्पतालों में गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे शासकीय अस्पतालों का औचक निरीक्षण करें। उन्होंने नर्सिंग होम एक्ट को और प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों के लिखे बिना दर्द निवारक दवाओं की बिक्री पर भी सख्ती से कार्यवाही करें।

बिलासपुर और जगदलपुर में शुरू होंगे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का कोई औचित्य नहीं नजर आ रहा है उस पर विचार किया जा रहा है। साथ उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में बिलासपुर और जगदलपुर में दो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 2 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने सोमवार को अंबेडकर अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने एडवांस कार्डियक इंस्टिट्यूट (एसीआई), क्षेत्रीय कैंसर संस्थान और नेत्र रोग विभाग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जायसवाल ने एसीआई में आईसीयू का निरीक्षण कर वहां भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने क्षेत्रीय कैंसर संस्थान में इलाजरत मरीजों के परिजनों से चर्चा कर उपचार और व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने यहां लीनियर एक्सीलरेटर और न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग का अवलोकन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने नेत्र रोग विभाग में अपने आंखों की जांच भी करवाई।

कट्टरपंथी मुस्लिम शरणार्थियों से यूरोप में बढ़ी मुसीबतें

योगेंद्र योगी

यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश लोकतांत्रिक, मानवाधिकारों की वकालत और उदारवादी चेहरा दिखाने के कारण मुस्लिम शरणार्थियों के कारण मुसीबत में फंस गए हैं। शरण लेने वाले मुस्लिम शरणार्थियों पर कट्टरपन हावी है। इन देशों के कानून मानने के बजाए शरणार्थी अपराधों में शामिल होने के साथ ही इस्लामी शासन की पैरवी कर रहे हैं। यही वजह है कि न सिर्फ युरोपीय यूनियन बल्कि उसके कुछ देशों ने साफ तौर पर मुसलमानों से देश छोड़ कर चले जाने को कहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने इस्लामिक संस्कृति को लेकर कहा कि यूरोप में इसके लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्लामी संस्कृति और हमारी सभ्यता के मूल्यों और अधिकारों के बीच कोई समानता नहीं है और यह एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि इटली में इस्लामी सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब फंड देता है, जहां शरिया लागू है। यूरोप में हमारी सभ्यता के मूल्यों से बहुत दूर इस्लामीकरण की एक प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि वह शरणार्थी सिस्टम में ग्लोबर रिफॉर्म पर जोर देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि शरणार्थियों की बढ़ती संख्या का खतरा यूरोप के कुछ हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। मेलोनी की तरह ही नीदरलैंड का प्रधानमंत्री बनते ही इस्लाम विरोधी नेता गीर्ट विल्डर्स ने उन मुसलमानों से देश छोडने का आह्वान किया कि जो धर्मनिरपेक्ष कानूनों से अधिक कुरान को महत्व देते हैं। विल्डर्स ने तो यहां तक कह दिया कि हिन्दुओं का समर्थन करूंगा जिन पर केवल हिंदू होने के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान में हमला किया जाता है या मारने की धमकी दी जाती है या फिर मुकदमा चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि मेरे पास नीदरलैंड के सभी मुसलमानों के लिए एक संदेश है जो हमारी स्वतंत्रता, हमारे लोकतंत्र और हमारे मूल मूल्यों का सम्मान नहीं करते हैं, जो कुरान के नियमों को हमारे धर्मनिरपेक्ष कानूनों से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। विल्डर्स ने कहा कि मुसलमानों की संख्या 7 लाख हैं और मेरा उन्हें संदेश है, बाहर निकलो। किसी इस्लामिक देश के लिए निकल जाओ। फिर, आप इस्लामी नियमों का आनंद ले सकते हैं। ये उनके नियम हैं, लेकिन हमारे नहीं हैं। शरणार्थियों की समस्या से गले तक भर चुके यूरोपीय देशों ने अब इस समस्या के समाधान के लिए नया समझौता किया है। यूरोपीय संघ और सदस्य देशों ने प्रवासन और प्रश्रय पर नए समझौते के जरिए अपनी प्रवासन नीति में सुधार करने का फैसला किया है। इसके तहत अनियमित रूप से आ रहे लोगों की त्वरित जाँच, सीमा पर डिटेंशन सेंटर बनाना और आवेदन अस्वीकृत होने पर शरणार्थियों को देश से बाहर करना आदि सुधार के रूप में शामिल है। हालाँकि अभी भी 27 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूरोपीय परिषद और यूरोपीय संसद द्वारा औपचारिक रूप से समझौते को मंजूरी देने की आवश्यकता है। जिसके बाद ही यह संभवत- वर्ष 2024 में ब्लॉक की कानूनी प्रक्रियाओं में शामिल हो पाएगा। गौरतलब है कि साल 2011 में सीरिया में शुरू हुए गृहयुद्ध के बाद लाखों सीरियाई और पड़ोसी मुल्कों से लोग भागकर यूरोप की शरण में आए थे। तभी यूरोपियन यूनियन ने वादा किया कि वो अपने देशों में लगभग 2 लाख रिफ्यूजियों को रखेगा। ग्रीस, इटली और फ्रांस में उस समय सबसे ज्यादा लोग भरे हुए थे। बाकी देश भी लोगों को स्वीकार करने लगे। इसके विपरीत पोलैंड की सरकार ने कहा था कि शरणार्थियों को रखना यानी अपनी ही तबाही के लिए बम फिट कर लेना है। पोलैंड का यह दृष्टिकोण फ्रांस और दूसरे देशों में सही साबित हुआ। एक मुस्लिम की युवक की मौत के बाद फ्रांस में जबरदस्त दंगे भड़क उठे। ट्रैफिक पुलिस द्वारा पेरिस में चेकिंग के दौरान नाहेल को पुलिस ने गोली मार दी थी। इस घटना में नाहेल की मौत हो गई थी। पुलिसकर्मियों का इस मामले पर कहना था कि लड़के के पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं था। चेकिंग के दौरान लड़के ने वाहन से ट्रैफिक पुलिस को कुचलने का प्रयास किया जिसके बचाव में लड़के को गोली मारी गई। इससे भड़की हिंसा की आग में फ्रांस कई दिनों तक जलता रहा। यूरोपियन इस्लामोफोबिया रिपोर्ट 2022 के मुताबिक पूरे यूरोप में इस्लाम के खिलाफ भावना तेजी से बढ़ रही है। यूरोपीय सरकारें इस्लाम और मुस्लिमों के खिलाफ क्रैकडाउन चला रहीं हैं। मस्जिदें बंद की जा रहीं हैं।

इंडी एलायंस की मजबूरी हैं नीतीश

अजय सेतिया

ललन सिंह का जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटना राष्ट्रीय चर्चा का मुद्दा बन गया, जबकि अपने आप में यह कोई बड़ी घटना नहीं थी। बिहार से बाहर तो कोई जानता ही नहीं था कि जेडीयू का अध्यक्ष कौन है, जेडीयू की पहचान सिर्फ नीतीश कुमार से है। अध्यक्ष कोई भी हो, पार्टी की कमान नीतीश कुमार के हाथ में ही होती है। जैसे अध्यक्ष कोई भी हो, कांग्रेस की कमान सोनिया-राहुल के हाथ में है, और अध्यक्ष कोई भी हो, भाजपा की कमान मोदी-शाह के हाथ में है।

नीतीश कुमार चाहते, तो वह ललन सिंह को हटाने के लिए पटना में ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलवा सकते थे। लेकिन उन्होंने कांग्रेस और इंडी एलायंस के बाकी घटक दलों को संदेश देने के लिए कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई। उन्हें कई दिन से एहसास हो रहा था कि कांग्रेस तो उनसे धोखा कर ही रही थी, लालू यादव भी धोखा देने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी स्तर पर कोई बातचीत शुरू नहीं हुई थी। फिर भी उन्होंने जेडीयू की दिल्ली में बैठक बुला कर यह संदेश दे दिया कि अगर कांग्रेस और इंडी एलायंस ने उन्हें वैसा सम्मान नहीं दिया, जिसके वह हकदार हैं, तो वह भाजपा के साथ जा सकते हैं।

भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी नीतीश कुमार की रणनीति से दहशत में आ गए थे, इसलिए उन्होंने अमित शाह का सितंबर में दिया गया भाषण याद करवाना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन उस भाषण की काट में यह दलील भी दी जाने लगी थी कि राजनीति में कुछ भी संभव है, किसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

नीतीश कुमार ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि भाजपा का साथ छोड़ना गलत फैसला था। और वह इसके लिए मुख्य तौर पर अपनी पार्टी के दो लोगों को जिम्मेदार मानते हैं। एक हैं पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह और दूसरे हैं ललन सिंह। दोनों नीतीश कुमार के आँख कान थे, एक पर भाजपा की गोदी में बैठने का आरोप लगा, तो दूसरे पर लालू यादव की गोदी में जा बैठने का आरोप लगा है। आरसीपी सिंह अब जेडीयू छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन ललन सिंह पार्टी के अध्यक्ष बने हुए थे। अब ललन सिंह का भी दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा हो गया है। वह अभी भी जेडीयू में बने हुए हैं, और इन आरोपों को पूरी तरह नकार रहे हैं कि उन्होंने लालू यादव के साथ मिल कर नीतीश कुमार का तख्ता पलटने की योजना बनाई थी।

खबर यह थी कि लालू यादव जेडीयू के 11-12 विधायक तोड़कर नीतीश कुमार का तख्ता पलट कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की साजिश रच रहे हैं, जिसमें ललन सिंह की अहम भूमिका है। क्या लालू यादव और ललन सिंह सचमुच ऐसा कर रहे थे? इसके पीछे की कहानी यह है कि नीतीश कुमार इंडी एलायंस में अपनी अनदेखी से तो निराश थे ही, लालू यादव जेडीयू के लिए 17 लोकसभा सीटें छोड़ने को भी तैयार नहीं थे। वह दुबारा भाजपा के साथ गठबंधन की संभावना टटोल रहे थे। 20 दिसंबर को राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की थी और उनसे आग्रह किया था कि वह लालू यादव के साथ मिल कर आपस में समस्याओं का हल निकालें। दोनों की मुलाक़ात हुई भी, लेकिन कोई हल नहीं निकला था। इसी बीच यह खबर बड़े जोर से उछली कि लालू यादव उनका तख्ता पलटने की योजना पर काम कर रहे हैं।

इन खबरों के बाद ही नीतीश कुमार ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का फैसला किया। जिसमें ललन सिंह का हटाया जाना इसलिए बड़ी खबर बना क्योंकि वह ललन सिंह और आरसीपी सिंह ही थे, जिनके कारण नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़कर लालू यादव और बाद में इंडी एलायंस का दामन थामा था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने इतनी भड़ास किसी अन्य पर नहीं निकाली, जितनी आरसीपी सिंह पर निकाली। ललन सिंह को हटाया जाना वैसे तो सिर्फ जेडीयू का अंदरूनी मामला है, लेकिन क्योंकि ललन सिंह जेडीयू-राजद गठबंधन के सूत्रधार थे, इसलिए इस फैसले के कई राजनीतिक संकेत थे। बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने वक्त रहते पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करवा कर बात को संभालने की पहल करने को कहा था। वह पहल हुई भी। सिर्फ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही नहीं बल्कि केसी वेणुगोपाल और शरद पवार ने भी नीतीश कुमार से बात करके स्थितियों को संभालने की कोशिश की।

लालू यादव तख्ता पलट की योजना से पीछे हटे हैं और नीतीश कुमार को इंडी एलायंस का संयोजक बनाने का फिर से वादा किया गया है। इसीलिए 27 दिसंबर की रात को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पास किए जाने वाले राजनीतिक प्रस्ताव की भाषा में बदलाव करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर हमलावर रूख अपनाया गया।अगर उन तीन चार दिनों में नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद करने का अलाप नहीं अलापा जाता तो राजनीतिक प्रस्ताव में उतनी कड़वी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता, जितनी कड़वी भाषा का इस्तेमाल किया गया। नीतीश कुमार के इस कदम से उनकी सरकार भी बच गई और इंडी एलायंस भी बच गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नीतीश कुमार पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह के खिलाफ जमकर बोले, जबकि वह जुलाई 2022 में ही पार्टी छोड़ चुके हैं। इसका कारण यह है कि नीतीश कुमार यह मानते हैं कि अगर आरसीपी सिंह ने उन्हें धोखा देकर सीधे मोदी से संबंध नहीं बनाए होते, तो उनके एनडीए छोड़ने की नौबत ही नहीं आती।

असल में इंडी एलायंस की नींव जुलाई 2021 में पड़ गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरसीपी सिंह को अपनी सरकार में मंत्री पद की शपथ दिलाई थी। नीतीश कुमार ने 2021 में मोदी सरकार में शामिल करने के लिए आरसीपी सिंह और ललन सिंह के नाम भेजे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेडीयू से एक ही मंत्री बनाना तय किया और बिना नीतीश कुमार से पूछे आरसीपी सिंह को शपथ दिला दी। यह बहुत ही आश्चर्यजनक था कि नीतीश कुमार से उनकी पहली चॉइस पूछने के बजाए अमित शाह ने उन्हें सूचना दी कि हम आरसीपी सिंह को मंत्री बना रहे हैं। उस समय ललन और आरसीपी दोनों ही नीतीश कुमार के करीबी थे, इसलिए उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। आरसीपी सिंह उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मंत्री बनने के तीसरे दिन नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा लेकर ललन सिंह को पार्टी अध्यक्ष बना दिया, लेकिन ललन सिंह के मन में यह बात बैठ गई थी कि आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को दरकिनार कर सीधे भाजपा से संबंध बना लिए हैं। बस यहीं से जेडीयू के एनडीए से निकलने की भूमिका तय हो गई थी।

ललन सिंह ने उसी दिन भाजपा से गठबंधन तोड़कर लालू यादव से गठबंधन बनाने की साजिश रचना शुरू कर दिया था। हालांकि वह ललन सिंह ही थे, जिन्होंने लालू यादव के चारा घोटाले की फाईल खोली थी, उन्हें भ्रष्टाचारी कह कर उनके खिलाफ आन्दोलन किया और आखिरकार उन्हें जेल पहुंचाया। लालू यादव के रेलमंत्री रहते समय हुए लैंड फॉर जॉब घोटाले को भी ललन सिंह ने खोला था, वह घोटाले के सबूत लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिले थे। लेकिन उन्हीं ललन सिंह ने ठान लिया था कि वह नीतीश कुमार का भाजपा से गठबंधन तुड़वा कर ही रहेंगे। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार से दूरी बना कर आग में घी डालने का काम किया। इस बीच बिहार के भाजपाई नेताओं का यह बयान नीतीश कुमार को नागवार गुजरा कि वह भाजपा की मेहरबानी से मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से शिकायत भी की थी, लेकिन किसी ने बिहार के नेताओं को नहीं रोका। तब नीतीश कुमार ने खुद ललन सिंह से कहा कि लालू यादव से बात की जाए। ललन सिंह ने लालू यादव से संपर्क किया और बात आगे बढ़ी। जुलाई 2022 में जब नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को राज्यसभा टिकट नहीं दिया, तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। नीतीश कुमार ने मोदी को कोई वैकल्पिक नाम नहीं भेजा और एक महीने के भीतर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर एनडीए से बाहर निकल गए। राज्यपाल को इस्तीफा देकर वह ललन सिंह के साथ ही सीधे राबड़ी देवी के घर पहुंचे थे, जहां लालू यादव और तेजस्वी यादव ने उनका दिल खोल कर स्वागत किया। लालू यादव ने भी ललन सिंह को माफ़ कर दिया। उस दिन से लालू और ललन के संबंधों में सुधार होता गया। नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ने के बाद विपक्षी एकता का बिगुल बजाना शुरू कर दिया था। जिसकी परिणिति 23 जून को पटना में विपक्ष की पहली बैठक में हुई, जो बाद में 28 दलों का इंडी एलायंस बना।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

पाशुपतब्रह्मोपनिषद् (भाग-2)

गतांक से आगे...

छियानवे तत्त्व तन्तुओं के रूप में व्यक्त होने वाला, चित् के तीन सूत्रों (सत्, चित् आनन्द) से चिन्मय लक्षणों वाला त्रिगुणित होने से नौ तत्त्वों वाला, ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप तीन अग्नियों से संयुक्त, चिद् ग्रन्थियों से बँधा हुआ, अद्वैत ग्रन्थि (ब्रह्मग्रन्थि) से युक्त यज्ञ के सामान्य अंग-रूप में बाह्य एवं अन्त:करण को प्रकाशित करने वाला यज्ञोपवीत, ब्रह्म के लक्षणों से युक्त हंस रूप है।

यहाँ यज्ञोपवीत की व्याख्या ब्रह्मसूत्र के रूप में की गई है। स्थूल यज्ञोपवीत का निर्माण जिन चेतन तत्त्वों के आधार पर किया जाता है, यहाँ उनका उल्लेख ऋषि कर रहे हैं। यज्ञोपवीत बनाने में चार अंगुलों अथवा उस माप को किसी वस्तु पर कच्चे सूत्र के तीन तारों को 96 बार लपेटा जाता है। उसे बटकर तिहरन करके पुन: बटते हैं। इस प्रकार एक लड़ में 9 तार हो जाते हैं। इसे तीन लड़ों वाले यज्ञोपवीत रूप में ग्रथित किया जाता है। प्रारंभिक ग्रंथियों के बाद अंत में ब्रह्मग्रन्थि लगाई जाती है। इन्हीं का विश्लेषण ऋषि ने किया है। अन्य बातें तो मन्त्रार्थ में स्पष्ट हैं, केवल 96 तत्त्वों का उल्लेख नहीं है। इसका स्पष्टीकरण सामवेदीय छान्दोग्य परिशिष्ट में इस प्रकार दिया गया है- तिथिवारञ्च नक्षत्रं तत्त्ववेदगुणान्वितम। कालत्रयं च मासाश्च ब्रह्मसूत्रं हि षण्णवम अर्थात् तत्त्व 25, गुण 3, तिथि 15, वार 7, नक्षत्र 27, वेद 4, काल 3 तथा मास 12 इस प्रकार कुल 96 तत्त्व वाला ब्रह्मसूत्र है। इस प्रकार यह उपवीत के लक्षणों से युक्त सूत्र (ब्रह्मसूत्र) यज्ञ रूप है अर्थात् यह ब्रह्म का प्रतीक रूप है। ब्रह्म के लक्षणों से युक्त यह यज्ञसूत्र (यज्ञोपवीत) है, वही ब्रह्मसूत्र है। अत: यज्ञोपवीत एवं ब्रह्मयज्ञ दोनों एक दूसरे के स्वरूप ही हैं। इसके अंग मात्राएँ हैं। यह ब्रह्मसूत्र ही इस मनोयज्ञ का हंस है। ब्रह्मयज्ञ से युक्त यह प्रणव भी ब्रह्मसूत्र ही है। प्रणव का अन्तर्वर्ती हंस भी ब्रह्मसूत्र है। यह ब्रह्मयज्ञ मोक्ष का साधन रूप ही है। [बाहर ब्रह्मसूत्र धारण करने का वास्तविक उद्देश्य अन्त:वर्ती ब्रह्मसूत्र को जाग्रत् जीवन्त बनाना होता है। जब अन्त:वर्ती ब्रह्मसूत्र परिपक्व अवस्था में पहुँच जाता है, तो बाह्यसूत्र को त्यागकर संन्यास में प्रवेश किया जाता है।]

क्रमश: ...

भारत की पहली शिक्षिका सावित्री बाई फुले

अंकित सिंह

भारत के इतिहास में ऐसे कई महिलाएं हैं जिनके द्वारा समाज में ऐसी भूमिकाएं निभाई रही हैं जिसका उल्लेख आज भी किया जाता है। हालांकि, यह बात भी सत्य है कि भारत के इतिहास में महिलाओं को वह प्रधानता नहीं मिली थी जिसकी वह हकदार थीं। लेकिन कुछ महिलाओं ने अपने कर्मों से समाज में अलग पहचान बनाई और आज की पीढ़ी के लिए वह एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हीं महान महिलाओं में से एक थी सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई बड़े काम किए थे। उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने पुणे में देश का पहला गर्ल्स स्कूल खोलकर समाज के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। यह उस वक्त की बात है जब भारतीय महिलाओं की स्थिति बड़ी ही दयनीय होती थी। लेकिन सावित्रीबाई फुले समाज सुधारक बनकर महिलाओं के जीवन में उत्थान लगने की कोशिश करती रहीं। उन्होंने समाज में शिक्षा और अवसरों के लिए कई बड़े प्रयास भी किए।

सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को नायगांव में हुआ था। तब या ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। अब महाराष्ट्र के सतारा में आता है। सावित्रीबाई फुले की शादी महज 10 वर्ष की उम्र में हो गई थी। सावित्री बाई के पति का नाम ज्योतिबा फुले था। सावित्रीबाई फुले समाज में महिलाओं की स्थिति को देखकर काफी निराश होती थीं। वह उनके लिए कुछ करना चाहती थीं। ऐसे में उन्होंने महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए 1948 में एक विद्यालय की शुरुआत की थी जिसमें 9 विद्यार्थी पढ़ते थे।

सावित्रीबाई फुले को कई विषयों का ज्ञान था। अपने पति के साथ मिलकर सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा और दलित उत्थान को लेकर कई बड़े काम किए। दोनों ने छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा को रोकने एवं विधवा पुनर्विवाह को प्रारंभ करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य भी किए। महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे करने के लिए सावित्रीबाई ने समाज में कई बड़े संघर्ष किए। हालांकि, वह अपनी इस काम में लगातार लगी रही। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर अट्ठारह स्कूल खोले थे। सावित्रीबाई ने अनेक विरोध सहे लेकिन वह अपने रास्ते से नहीं भटकीं। पूरी निडरता के साथ समाज को कुरीतियों से बाहर निकालने की कोशिश करते रहीं। सावित्रीबाई फुले ने बाल विवाह और युवा विधवाओं के मुंडन के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद की थी। बताया जाता है कि सावित्रीबाई ने पहला विधवा पुनर्विवाह 25 दिसंबर 1873 को संपन्न कराया था। बताया जाता है कि सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने के लिए अपने घर से निकलती थी, तब लोग उन पर कीचड़, कूड़ा और गोबर तक फेंकते थे।

भारत ग्लोबल साउथ को कर सकता है एकजुट

शंकर अय्यर

दुनिया समय और घटनाओं के मोड़ पर है। नए वर्ष में प्रवेश के बीच, उभरते संकटों ने नाराजगी और संशय के साये को जन्म दिया है। अंतहीन युद्ध और राष्ट्रीय हित की पुनर्परिभाषा विकास की संभावनाओं को धूमिल कर रही है। ऐसी धारणा बढ़ती जा रही है कि नियम आधारित विश्व व्यवस्था वैश्विक अव्यवस्था में बदल रही है। यह संदर्भ भारत के लिए मायने रखता है कि वह परस्पर एक-दूसरे पर निर्भर दुनिया में कैसे अपनी क्षमता को आगे बढ़ाता है। जैसे-जैसे हम प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के चुनावी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, भू-राजनीति की विषमताएं सामने आ रही हैं। भारत को इससे बचना होगा और खुलकर अपने विकल्पों पर विचार करना होगा। बहस के लिए परिस्थितियां तैयार करने का एक उपयोगी लेंस नए वर्ष पर संकल्प लेने की परंपरा है। इस परंपरा का सार चिंतन, पहचान और पुनर्स्थापना है। राष्ट्रीय आयात के मुद्दों पर और भू-राजनीतिक क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने और उसका लाभ उठाने के मुद्दों पर सफलता आम सहमति बनाने की कला में निहित है।

यहां कुछ प्रस्ताव सुझाए गए हैं, जिनकी शुरुआत उन बहुपक्षीय एजेंसियों में सुधारों से होती है, जिन्हें नियम-आधारित विश्व व्यवस्था को मजबूत करने का काम सौंपा गया है और जिस पर भारत ने काफी समय और श्रम खर्च किया है। संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी अपवाद संस्था है, जो उत्तरोत्तर अपनी प्रासंगिकता घटाती जा रही है। इसी कारण आज दुनिया भर में 30 से अधिक संघर्ष के क्षेत्र बन चुके हैं। यूक्रेन युद्ध में किसी के विजेता होने की उम्मीद नहीं है और लगभग हर कोई चाहता है कि गाजा में युद्ध खत्म हो। शांति बाध्यकारी और गैर-बाध्यकारी संकल्पों में उलझी हुई है और उसे वीटो की ताकत वाले उन देशों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो वैश्विक आबादी के छठे हिस्से से भी कम का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र में न्यायसंगत प्रतिनिधित्व और सुधारों के लिए समझौता करने और वीटो धारक देशों से निपटने के लिए जी-20 की तरह ग्लोबल साउथ को एकजुट कर सकता है।

भारत का उदय स्वाभाविक रूप से निगरानी और खतरों को जन्म देता है, क्योंकि घरेलू राजनीति भू-राजनीति को प्रभावित करती है। कामकाज की शैली और प्रतिक्रियाओं के मापांकन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। भावनात्मक विश्लेषण के इस युग में लाठियां और पत्थर तो हड्डियों को चोट पहुंचाएंगे, लेकिन शब्द कलंकित कर सकते हैं। भारत को दुनिया भर में अपने विदेशी सेवा कैडर का विस्तार करने की जरूरत है, ताकि वे उन परिभाषाओं पर सहयोग कर उन्हें फिर से तैयार करने में मदद कर सके, जो मायने रखती हैं। इसके लिए सक्रिय ढाल बनाने, अप्रासंगिक सिद्धांतों का मुकाबला करने और दोहरेपन को उजागर करने की आवश्यकता है। दोहा के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की विफलता के बाद से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का मृत्युलेख लिखा जा रहा है। मुक्त व्यापार के विचार को इसके प्रचारकों ने ही त्याग दिया है, जो अब संरक्षणवाद की वकालत कर रहे हैं। डब्ल्यूटीओ की अपीलीय संस्था 2020 से मृत है और मध्यस्थता सहयोगी व्यापारिक गुटों तक सीमित है। कैनकन में हुई मंत्रिस्तरीय बैठक की तरह भारत को डब्ल्यूटीओ की वैधता को फिर से जिलाने के लिए अर्थव्यवस्थाओं का गठबंधन बनाने की जरूरत है। बेहतर दिशा में पहला कदम उठाने से अगले मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करने और अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में गठित दो संस्थानों, आईएमएफ और विश्व बैंक, ने उस समय के उद्देश्य पूरे कर लिए हैं। अतएव नई वास्तविकताओं के अनुरूप इनकी भूमिकाओं को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। भारत डिजिटल बुनियादी ढांचे में अग्रणी और पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में भारत के पास सहयोग करने और एक नया ढांचा पेश करने का अवसर है। आईएमएफ को राहत पैकेज से आगे बढ़कर आने वाले संकटों की भविष्यवाणी करने के लिए डाटा पेश करने और लचीलेपन के लिए नीतियां तैयार करने की जरूरत है। जबकि विश्व बैंक को अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव को वित्तपोषित करने के लिए नए ढंग से स्थापित किया जाना चाहिए।

चूंकि भारत वैश्विक बदलाव का भागीदार है, उसे अपने विकास को बनाए रखने के लिए घरेलू स्तर पर क्षमता तैयार करने और लचीलेपन की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान से पता चलता है कि अगले चार दशकों तक भारत की कामकाजी आबादी घटने वाली नहीं है। लेकिन जनसांख्यिकी नियति नहीं है। भारत को व्यवसाय मॉडल में विघटनकारी बदलाव के खातिर तैयार रहने के लिए मानव पूंजी में निवेश करना चाहिए। स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर अधिक खर्च करने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। गारंटी के इस दौर में क्या राजनीतिक दल स्वास्थ्य, शिक्षा व कौशल विकास के लिए धन खर्च करने पर प्रतिबद्धता जताएंगे?

जनमत सर्वेक्षणों में बेरोजगारी शीर्ष चिंता का विषय है। नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से पता चलता है कि 45 प्रतिशत से अधिक श्रमिक कृषि से प्राप्त राष्ट्रीय आय के छठे हिस्से पर निर्भर हैं और मात्र 11 फीसदी लोग विनिर्माण नौकरियों पर निर्भर हैं। संरचनात्मक रूप से केवल 20.8 फीसदी श्रमिक ही नियमित वेतन पर काम करते हैं, 22 फीसदी आकस्मिक मजदूर हैं। जनसांख्यिकीय उभार का उल्टा होना राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों व विनियमों में सुधार और निवेश शिखर सम्मेलन के साथ पीएलआई योजनाओं जैसी नीतियों के तालमेल पर निर्भर करता है। और हां, रोजगार सृजन की बेहतर मैपिंग इसमें मदद करेगा, जो नीति आयोग के लिए उपयुक्त कार्य है।

भारत वादे और प्रदर्शन के चौराहे पर खड़ा है। सफलता राष्ट्रीय हित पर विभिन्न पार्टियों के बीच सहमति पर निर्भर करती है। इसके लिए घरेलू राजनीति में संवाद की बहाली जरूरी है। संसद में हुआ तमाशा और पार्टी हित पर जोर चिंताजनक है। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि अगर चीजें गलत होती हैं, तो यह खराब संविधान के कारण नहीं, बल्कि %बुरे लोगों% के कारण होंगी। भारतीय राजनीति में अच्छे लोगों को अवश्य सामने आना चाहिए।

आज का इतिहास

1955 जोस रामन गुइजाडो पनामा के राष्ट्रपति बने।
1956 फ्रांस में एफिल टॉवर के ऊपरी हिस्से में आग लगने से नुकसान हुआ।
1957 अमेरिका के पेनसिल्वेनिया में पहली बार बिजली घड़ी प्रदर्शित की गयी।
1957 हैमिल्टन वॉच कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक वॉच का उद्घाटन किया।
1959 अलास्का को अमेरिका का 49वां राज्य घोषित किया गया।
1961 फिनलैंड के सबसे खराब नागरिक विमान दुर्घटना में पच्चीस लोगों की मौत हो गई जब एयरो फ्लाइट 311 केव्लैक्स के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
1971 बीबीसी ने विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम में शुरू किया।
1973 अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज स्टीनब्रेनर और निवेशकों के एक समूह ने न्यूयॉर्क यैंकीज की पेशेवर बेसबॉल टीम को .8.7 मिलियन के लिए खरीदा।
1976 आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय करार, मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक का हिस्सा था।
1990 पनामा-जनरल मैनुअल नोरिएगा के संयुक्त राज्य पर आक्रमण, जो कि %पनामा के मजबूत आदमी% थे, ने अमेरिकी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
1994 13 साल के प्रदर्शन के बाद ब्यूमोंट थिएटर न्यूयॉर्क शहर में प्रसिद्ध शेर ग्रे एनाटॉमी बंद हो गया।
1996 पहला मोबाइल फोन मोटोरोला स्टारटैक जारी किया गया और व्यापक उपभोक्ता अपनाने के बाद यह पहला मोबाइल फोन बन गया।
1997 ज़िम्बाब्वे के एडडो ब्रांड्स हरारे में एकदिवसीय हाट-ट्राइकस बनाम इंग्लैंड ले जाता है।
1998 अल्जीरियाई इस्लामी विद्रोह में 412 लोगों की हत्या हुई।
2004 मिस्र की विमानन कंपनी फ्लैश एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान 604 के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार सभी 148 लोग मारे गये।
2009 इज़राइल ने गाजा पट्टी पर आक्रमण शुरू किया।

क्या तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की जमीन तैयार है?

अतुल सिन्हा

लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले जिस तरह बिहार की राजनीति में तूफान आया है उससे यह तो संकेत मिलने लगे हैं कि बिहार में जल्दी ही सत्ता परिवर्तन का खेल शुरु हो सकता है। अगर भाजपा सांसद और केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यह कह रहे हैं कि लालू यादव 14 जनवरी से पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवा देंगे, तो इसके आसार भी नजर आने लगे हैं। आरजेडी खेमे में जबरदस्त हलचल है। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने साल के आखिरी दिन लालू यादव से राबड़ी देवी के घर पर मुलाकात की। तेजस्वी ने भी अपना जनवरी के पहले हफ्ते में प्रस्तावित आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा रद्द कर दिया है।

2020 के चुनाव नतीजों को याद कीजिए। 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी उभरी थी। भाजपा को 74 सीटें मिली थीं। बाद में ओवैसी की पार्टी के पांच में से चार विधायक भी आरजेडी में शामिल हो गए और आरजेडी के कुल 79 विधायक हो गए। कांग्रेस के 19 विधायक चुने गए थे जबकि वामपंथियों के 16 विधायक। दूसरी तरफ एनडीए के साथ चुनाव लड़ने वाले जेडीयू को केवल 45 सीटों पर संतोष करना पड़ा और भाजपा को 74 सीटें मिली थीं, हालांकि अब उसके 78 विधायक हैं। तब भी तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के सबसे पहले दावेदार थे। लेकिन नीतीश ने खुद मुख्यमंत्री बने रहने के लिए भाजपा के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई। यह तकलीफ लालू यादव को तब से ही रही है। लेकिन नीतीश ने मुख्यमंत्री बनने के डेढ़ साल बाद ही फिर पाला बदला, लालू यादव की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और तीन ही महीने बाद अगस्त 2022 में एनडीए छोड़कर फिर से आरजेडी के साथ चले गए। मुख्यमंत्री वह बने रहे और तेजस्वी यादव को 2015 की तरह उप मुख्यमंत्री के तौर पर संतोष करना पड़ा। लेकिन अगर गिरिराज सिंह की मानें तो लालू यादव पहले से ही वक्त के इंतजार में थे और चुनाव से पहले 'खेला' करने की रणनीति बना चुके थे।

आरजेडी से जुड़े एक नेता का कहना है कि सियासत के खेल में लालू यादव हमेशा से नीतीश पर भारी रहे हैं। उनके कहने पर ही नीतीश ने मोदी

सरकार के खिलाफ महागठबंधन बनाने की पहल की। लालू ने ही नीतीश को यह समझाने की कोशिश की कि अब वह मुख्यमंत्री बहुत रह लिए, उन्हें तो प्रधानमंत्री होना चाहिए और इसके लिए महागठबंधन ही एकमात्र रास्ता है। नीतीश ने इसके लिए खूब मेहनत की, ममता बनर्जी से लेकर सोनिया गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल तक से मिले। सबको जोड़ा और इंडिया गठबंधन अब चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए तैयार है। आखिरकार 19 दिसंबर की इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान जब बतौर पीएम मल्लिकार्जुन खरगे का नाम प्रस्तावित हुआ तब ये सवाल उठने लगे कि अब नीतीश क्या करेंगे। उनकी गठबंधन में क्या भूमिका होगी, क्या वे गठबंधन के संयोजक बनेंगे या फिर एक बार फिर एनडीए का रुख करेंगे। इस आशंका को 29 दिसंबर को जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक के बाद हुई केसी त्यागी की प्रेस कांफ्रेंस ने और हवा दी, जब उन्होंने यह कह दिया कि राजनीति में न तो कोई दोस्त होता है, न दुश्मन। साथ ही उन्होंने निमंत्रण मिलने पर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी जाने की बात कह दी।

हालांकि कार्यकारिणी की बैठक में मोदी सरकार के खिलाफ सख्त भाषा में प्रस्ताव भी पारित हुए, विपक्षी सांसदों के निलंबन पर भी मोदी सरकार के रवैये की तीखी आलोचना की गई, साथ ही नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग के लिए अधिकृत किया गया। इसके बावजूद ये अफवाहें उड़ती रहीं कि नीतीश फिर पलटी मार सकते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के किसी भी घटक दल के किसी भी नेता ने कभी ये बात नहीं की और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। लेकिन नीतीश को केन्द्रीय भूमिका में लाकर बिहार के मुख्यमंत्री का ताज तेजस्वी को पहनाने की पटकथा काफी पहले से लिखी जा रही थी और यह तभी संभव था जब नीतीश की भूमिका पार्टी में और गठबंधन में और बढ़ाई जाए। हालांकि जिस तरह तेजस्वी यादव के खिलाफ ईडी के सम्मन लगातार आ रहे हैं, उससे यह तो संकेत मिल ही रहे हैं कि केन्द्र की गहरी नजर बिहार पर है और अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश होती है तो वह अपनी कार्रवाइयां और तेज कर सकती है।

अगर बिहार विधानसभा में विधायकों की मौजूदा स्थिति पर गौर करें तब साफ हो जाएगा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुल 243 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत है। आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, भाकपा माले के 12, भाकपा और माकपा के 4 विधायकों को मिला लें तो कुल संख्या 114 ही होती है। यानी 8 विधायकों की और जरूरत होगी। अगर एक निर्दलीय और एआईएमआईएम के एक विधायकों को जोड़ लें तब भी यह संख्या 116 ही होती है। जाहिर है, ऐसे में जेडीयू के बगैर ये संभव नहीं हो पाएगा। लालू यादव फिलहाल इसी कोशिश में हैं। और इसके लिए वह इंडिया गठबंधन की मजबूती के नए आयाम तलाशने में लगे हैं।

दरअसल 19 दिसंबर को दिल्ली से लौटते वक्त लालू यादव केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की मुलाकात और झटका मटन खिलाने के सियासी बयान के बाद से ही यह कहानी शुरु हुई। तब से ही लगातार गिरिराज सिंह ऐसी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले तेजस्वी यादव भी साफ कर चुके हैं कि विमान में गिरिराज की बगल वाली सीट पर वह खुद मौजूद थे। तेजस्वी ने यह भी खुलासा किया था कि गिरिराज सिंह खुद अपने केन्द्रीय नेतृत्व से दुखी हैं और अपना टिकट कट जाने की आशंका से डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जिस तरह की राजनीति करते हैं, उससे सभी वरिष्ठ नेता परेशान हैं और पार्टी में उनकी कोई हैसियत नहीं है। पार्टी अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद से नीतीश कुमार भी खासे सक्रिय हैं। उन्होंने यह साफ कर दिया है कि उनके और ललन सिंह के बीच कोई विवाद नहीं है और ललन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अब जेडीयू का विस्तार करना है और इसके लिए वह झारखंड से अपनी यात्रा भी शुरु करने वाले हैं।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सेवी राधाबाई

शशांक शर्मा

प्रसिद्धि स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक राधा बाई ने एक ओर स्वतंत्रता संग्राम में अनेक जेल यात्राएँ कीं वहीं सामाजिक जागरण विशेषकर वेश्यावृत्ति के लिये विवश की जाने वाली महिलाओं के उत्थान और आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक सम्मान की दिशा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। राधाबाई महाराष्ट्र की रहने वालीं थीं । उनका पूरा जीवन छत्तीसगढ़ में बीता । वे पेशे से नर्स थीं लेकिन अपने पूरे परिवेश में डाक्टर राधाबाई के नाम से प्रसिद्ध थीं। वे 1930 से स्वतंत्रता के लिये किये जाने वाले अहिसंक आँदोलन से जुड़ीं और उन्होंने 1942 तक हर सत्याग्रह में भाग लिया एवं जेल गईं। राधाबाई का जन्म 1875 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। तिथि का उल्लेख नहीं मिलता। जब वे मात्र नौ वर्ष की थीं तब 1884 में उनका बाल विवाह हो गया था। पर उनका दाम्पत्य जीवन नहीं चल सका। उनकी पहली विदा होने से पहले ही पति की मृत्यु हो गई। किसी बीमारी में माता पिता की भी मृत्यु हो गई। उनका पालन पोषण पड़ौसिन ने किया। समय के साथ परिश्रम आरंभ किया और दाई का काम सीखा। समय के साथ प्राकृतिक जड़ी बूटियों से उपचार करना भी सीख लिया। वे गर्भस्थ महिलाओं की छोटी मोटी समस्याओं का उपचार जड़ी बूटियों से कर देतीं थीं और उनके साथ के प्रसव भी सफल होते । इसलिये अपने आसपास डाक्टर राधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हो गईं। वे 1918 में रायपुर आईं और नगरपालिका में दाई का काम करने लगीं। प्रसव पीड़िताओं के साथ उनका व्यवहार, गुणवत्ता के कारण वे बहुत लोकप्रिय हो गईं। सन 1920 में महात्मा गाँधी पहली बार रायपुर आये, गाँधी जी सभा हुई। वे सभा सुनने गईं और आँदोलन से जुड़ गईं। तब से राधाबाई ने हर प्रभात फेरी और सभाओं में न केवल भाग लेतीं अपितु प्रचार कार्य में जुड़ गई। 1930 में पहली बार गिरफ्तार हुईं और इसके बाद उन्होंने 1942 तक हर सत्याग्रह भाग लिया। अनेक बार जेल गईं। स्वतंत्रता आँदोलन के साथ उन्होंने दो अभियान चलाये एक अस्पृश्यता निवारण का और दूसरा कामगारों की बस्ती में सफाई अभियान। वे सफाई कामगारों की बस्ती में जाती और स्वयं केवल सफाई ही नहीं करतीं थीं अपितु उनके बच्चों को नहलाने और पढ़ाने का काम भी करतीं थीं। उन्होंने उन बस्तियों में ही ऐसे कार्यकर्ता तैयार किये जो सफाई और बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करने लगे। वे केवल रायपुर नगर तक ही सीमित न रहीं। एक टोली बनाकर आसपास भी जातीं। उन्होने धमतरी तहसील के अंतर्गत कंडेल गाँव में एक चरखा केन्द्र भी खोला। चरखा वे स्वयं भी चलातीं और चरखे से खादी तैयार कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करतीं। उन्होने चरखा पर अनेक गीत तैयार किये तथा चरखा चलाने के साथ सब के साथ गीत भी गातीं मेरे चरखे का टूटे न तार, चरखा चालू रहे। चरखा सिखाने के लिये उन्होने एक टोली भी तैयार की जिसमें पार्वती बाई, रोहिणी बाई, कृष्ण बाई, सीता बाई, राजकुँवर बाई आदि थीं। ये सभी महिलाएँ 1942 के भारत छोड़ो आँदोलन में जेल भी गईं। उन दिनों छत्तीसगढ़ में महिलाएँ ब्लाउज नहीं पहनतीं थीं। जबकि महाराष्ट्र विशेषकर नागपुर में पहना जाता था। राधाबाई ने महिलाओं को ब्लाउज पहने के लिये प्रेरित किया। उन्हे अपने समय के सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित सुन्दर लाल की पत्नि की पत्नि श्रीमती बोधनी बाई का साथ मिला और महिलाओं में जाग्रति अभियान तेज चलने लगा। उन दिनों छत्तीसगढ़ में एक प्रथा किसबिन नाचा थी । यह एक प्रकार की वेश्यावृत्ति थी राधाबाई ने इस प्रथा के उन्मूलन का काम आरंभ किया। राधाबाई ने इस पृथा के उन्मूलन की शुरुआत 1944 से आरंभ की थी और अपने जीवन की अंतिम श्वाँस तक करती रहीं। वस्तुतः छत्तीसगढ़ के गाँवों और नगरों में एक सामंती प्रथा थी जिसमें नृत्य के लिये जो महिलाएँ आतीं थीं उनका शारीरिक शोषण भी होता था। इसे किसबिन नाचा कहा जाता था। किसबिन नाचा करने वालों का एक वर्ग ही बन गया था। जैसे राजस्थान और मालवा में कभी बाछड़ा वर्ग हुआ करता था। वैसे ही छत्तीसगढ में यह किसबिन नाचा वर्ग बन गया था । इस वर्ग के लोग अपने ही परिवार की लड़कियों को %किसबिन नाचा% के काम में लगा देते थे। इस वर्ग की लड़कियाँ भी मानों यही काम अपनी नियति समझती थीं। राधाबाई और उनकी टोली ने इस प्रथा को समाप्त करने का अभियान चलाया । इसकी शुरुआत खरोरा नामक गाँव से हुई । महिलाओं को चरखा चलाने के काम में लगाया और पुरुषों को खेती-बाड़ी के काम में। यह परिवर्तन राधाबाई के कारण ही संभव हुआ । इसके लिये स्वतंत्रता के बाद राधा बाई का सम्मान किया गया । अपना पूरा जीवन समाज और राष्ट्र को समर्पित करने वाली राधाबाई का निधन 2 जनवरी,1950 को हुआ । वे अकेली रहतीं थीं। उन्होंने जीवन काल में अपना मकान अनाथालय को देने की बसीयत कर दी थी । उनके निधन के बाद उनकी बसीयत के अनुसार उनका मकान एक अनाथालय को दे दिया गया ।

2024 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को रोकना लगभग असंभव

नितिन गौतम

लोकसभा चुनाव में कुछ ही माह का समय बचा है और सभी राजनीतिक पार्टियां आम चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। इस बीच ब्रिटेन के प्रमुख अखबार द गार्जियन में एक लेख लिखा गया है, जिससे विपक्षी पार्टियों को निराशा हो सकती है। दरअसल लेख में दावा किया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनना तय है और इसे कोई नहीं रोक सकता। यह लेख हन्नाह एलिस पीटरसन ने लिखा है। पीटरसन लिखती हैं कि %तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली जीत से मिले आत्मविश्वास, पीएम मोदी की लोकप्रियता और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते भाजपा का लगातार तीसरी बार सत्ता में आना तय है और इसे रोकना लगभग असंभव है। तीन राज्यों में मिली जीत के बाद खुद पीएम मोदी भी 2024 में जीत की भविष्यवाणी करने से खुद को नहीं रोक पाए।% लेख के अनुसार, भारत के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच एक तरह की सहमति है कि पीएम मोदी और भाजपा की जीत होनी तय है। पीटरसन लिखती हैं कि %प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और उनकी मजबूत नेता की छवि के साथ ही भाजपा के हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे से बड़ी संख्या में हिंदू मतदाता प्रभावित हैं, खासकर उत्तर भारत की हिंदी बेल्ट में भाजपा खास तौर पर मतदाताओं को लुभा रही है। साल 2014 के बाद से राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर देश का जनमत बड़े पैमाने पर भाजपा की तरफ झुका है। लेख में लिखा गया है कि भारत के दक्षिण और पूर्व के हिस्से में विपक्षी पार्टियां भाजपा के मुकाबले मजबूत हैं लेकिन राष्ट्रीय तौर पर विपक्ष बिखरा हुआ और कमजोर नजर आ रहा है। गार्जियन के लेख में कांग्रेस को लेकर लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हालिया विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में जीती है लेकिन यह अभी तीन राज्यों में ही सत्ता में है और पार्टी अंदरुनी कलह से जूझ रही है। विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन किया है लेकिन अभी भी विपक्षी पार्टियों को कई अहम मुद्दों पर सहमत होना बाकी है। हालांकि ये सभी पार्टियों भाजपा के खिलाफ लड़ने एकजुट होकर लड़ने की बात कर रही हैं। सामान्य सोच यही है कि अभी भाजपा की जीत तय लग रही है। लेख के अनुसार, पीएम मोदी साल 2014 में सत्ता विरोधी लहर के सहारे सत्ता में आए थे। वहीं 2019 की जीत में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर एयरस्ट्राइक के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा का भाव उनके पक्ष में गया और उन्हें जीत मिली। हालांकि यह साफ नहीं है कि क्या भाजपा इस बार 2019 के बहुमत को दोहरा पाएगी या नहीं। भाजपा की राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत पीएम मोदी की लोकप्रियता का सबूत है। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने रणनीतिक रूप से प्रधानमंत्री के चेहरे को प्राथमिकता दी ना कि स्थानीय नेताओं को। प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव में दर्जनों रैलियां की और खुद लोगों से पार्टी के लिए वोट मांगा। पीएम मोदी की वोट की अपील का आधार भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ ही उनका राष्ट्रवादी एजेंडा रहा।

कांग्रेस के लिए 2024 आर या पार की तरह है

संजीव चोपड़ा

हिंदी भाषी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में मिली असफलताओं के बाद कांग्रेस 18वीं लोकसभा के लिए 2024 में होने वाले चुनाव में 'आर या पार' के लिए तैयार है। जहां नरेन्द्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करके पंडित जवाहर लाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं कई लोग वर्ष 2024 को कांग्रेस के लिए उसकी 138 साल की यात्रा में सबसे कठिन अवधि में से एक के रूप में भी देख रहे हैं। वर्ष 1984 में रिकॉर्ड 414 लोकसभा सीट जीतकर कांग्रेस के अपने चुनावी शिखर को छूने के चार दशक भी पूरे हो जाएंगे। संसद के निचले सदन में कांग्रेस के केवल 48 सदस्य ही हैं और इस प्रकार पार्टी को पिछले 10 वर्षों में लगातार गिरावट देखने को मिली है।

कांग्रेस अपनी सीट की संख्या में आ रही लगातार गिरावट को 2024 में रोकने की उम्मीद कर रही है, लेकिन इसके लिए उसे विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है भाजपा-विरोधी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस' (इंडिया) के घटक दलों के साथ सीट-बंटवारा समझौते को अंतिम रूप देना। इस गठबंधन का अभी तक कोई चुनावी प्रभाव तो नहीं दिख सका है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी-भाषी राज्यों में भाजपा के हाथों सत्ता गंवाने और मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी में विफल रहने वाली कांग्रेस जब सीट बंटवारे को लेकर बातचीत करेगी तो उसकी स्थिति कमजोर नजर आएगी।

हार के कारण कांग्रेस का आकलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है, क्योंकि वह 2022 में हिमाचल प्रदेश

और 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनावों में जीत से प्राप्त गति बनाए रखने की उम्मीद कर रही थी। वर्ष 2024 के आम चुनावों से ठीक पहले इस हार के पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी निराशाजनक साबित होने की संभावना है, क्योंकि हिंदीभाषी राज्य चुनाव परिणाम निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2019 में भाजपा ने हिंदी पट्टी में 141 सीट पर जीत हासिल की थी, जो इस क्षेत्र की कुल सीट का 71 फीसदी था। एक चुनाव विश्लेषक का मानना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह दो आम चुनाव बुरी तरह हार चुकी है। विश्लेषक ने कहा, अब पार्टी के लिए यह आर या पार वाली स्थिति है।

कांग्रेस अब केवल तीन राज्यों- हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना- में अपने दम पर सत्ता में है, जबकि हिमाचल प्रदेश एकमात्र उत्तर भारतीय राज्य है, जहां अब इस पार्टी का शासन है। हिमाचल प्रदेश में केवल चार लोकसभा सीट है। हालांकि, दक्षिणी राज्यों में पार्टी मजबूत होती दिख रही है। हिंदी पट्टी से लगभग सफाया होने के बाद, कांग्रेस को मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए नयी योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता होगी। भाजपा ने कांग्रेस की मुफ्त योजनाओं और जातिगत गणना के मुद्दे की काट के तौर पर क्रमशः 'मोदी की गारंटी' और प्रधानमंत्री की 'चार जातियों- महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों' को खड़ा किया है। जातिगत गणना, मुफ्त की रेवड़ियां और अडाणी-विरोधी अभियान सहित कांग्रेस के विभिन्न अपीलों का जनता पर कोई व्यापक असर नहीं हुआ है और फलस्वरूप पार्टी लोगों के साथ फिर से जुड़ने की उम्मीद में राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' के दूसरे संस्करण की घोषणा कर चुकी है। मणिपुर से महाराष्ट्र तक हाइब्रिड (बस और पैदल) 'भारत न्याय यात्रा' 14 जनवरी को शुरू होगी और 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। इसे इंफाल से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हरी झंडी दिखाएंगे और यह नगालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरकर 6,200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

इस यात्रा को आगामी अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनावों की घोषणा यात्रा के अंतिम चरण के वक्त हो सकती है। कांग्रेस ने चुनाव की अपनी तैयारी दर्शाते हुए स्थापना दिवस के अवसर पर नागपुर में 'हैं तैयार हम' रैली आयोजित की थी। पार्टी पिछले कई दिनों से लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर राज्य के नेताओं के साथ विचार-विमर्श कर रही है और अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस जहां अपनी किस्मत पलटने को लेकर उत्साहित है, वहीं आने वाली चुनौतियों के प्रति पूरी तरह सचेत भी है। 'इंडिया' गठबंधन के भीतर सफल सीट-बंटवारे को लेकर बातचीत में पहली बाधा पार्टी के भीतर से आई है, क्योंकि इसकी पंजाब और दिल्ली इकाइयों ने आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी समझौते के खिलाफ खुले तौर पर चेतावनी दी है।

बीते वर्ष में आत्मनिर्भर बनने के संकल्प के पथ पर भारत ने नई रेखाएं खींची

ललित गर्ग

बीते वर्ष में सकारात्मकता की नयी तस्वीरें सामने आयी। ज्यादातर बड़ी सकारात्मक खबरें आर्थिक उपलब्धियों और नये राजनीतिक समीकरणों से जुड़ी हैं। साल के अंत में हुए विधानसभा चुनावों, महिला सशक्तीकरण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, नए संसद भवन के उद्घाटन, हर क्षेत्र में स्वदेशी की शक्ति और संसदीय-राजनीति, सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसलों, चंद्रयान-3 और आदित्य एल-1 मिशन जैसी वैज्ञानिक उपलब्धियां निराशा से ज्यादा आशाभरी खबरों ने आजादी के अमृतकाल में वास्तविक रूप में अमृतमय होने के संकेत दिये हैं। भारत की दिशा एवं दशा बदल रही है। बीते वर्ष में राजनीति से लेकर सामाजिक, आर्थिक से लेकर खेल तक, सुरक्षा से लेकर सौहार्द तक अनेक सकारात्मक दृष्टिकोण ने सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास को बल दिया है।

चीन के हैंगजाऊ में हुए एशियाई खेलों में कई प्रकार के रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने खेल की दुनिया में बड़ा कदम रखा। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है पदक तालिका में 'सौ से अधिक पदक' प्राप्त करना करना। यह उपलब्धि देश के आकार को देखते हुए पर्याप्त नहीं है, पर पिछले प्रदर्शनों से इसकी तुलना करें, तो बहुत बड़ी है। यह भारत के विकसित होते बदलते सामाजिक-आर्थिक स्तर को भी रेखांकित कर रही है। शेयर मार्केट तमाम कयासों को झुठलाते हुए उच्चस्तर पर बना हुआ है। जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा हुआ है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 15 दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह में 20 माह के उच्चतम स्तर 616 अरब डॉलर हो गया है। 25 मार्च, 2022 के बाद का यह उच्चतम स्तर है। आत्मनिर्भर बनने के संकल्प के पथ पर दौड़ रहे भारत ने हर क्षेत्र में स्वदेशी का लोहा मनवाया है। हमने युद्धपोत और हल्के लड़ाकू विमान से लेकर घातक ड्रोन तक बनाया है। देश में इस्तेमाल होने वाले 99 प्रतिशत मोबाइल हम खुद बना रहे हैं। अपने बूत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर भारत ने पूरी दुनिया को चौंकाया है। 85 से अधिक देशों को भारत स्वदेशी हथियार, उपकरण, ड्रोन, कलपुर्जे निर्यात कर रहा है। रक्षा उत्पादों में हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। रक्षा उत्पादों के निर्यात में वर्ष 2013-14 की तुलना में 23 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गयी है। प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि अपनी बुद्धि से साधु होना अच्छा, पराई बुद्धि से राजा होना अच्छा नहीं। लेकिन हम अपनी बुद्धि, कौशल एवं तकनीक से राजा बन रहे हैं।

वर्ष 2023 महिलाओं की दृष्टि से ऐतिहासिक रहा। खेल, राजनीति, विज्ञान, व्यापार जैसे क्षेत्रों में महिलाओं ने खूब नाम कमाए हैं। देश में सावित्री जिन्दल का नाम सबसे धनाढ्य महिलाओं में सामने आया, इसी तरह अनेक महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में नये कीर्तिमान गढ़ रही है। इस वर्ष में महिला सशक्तीकरण का बिगुल तब बजा जब सितंबर माह में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का उद्घोष हुआ। संसद में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की घोषणा की, यह ऐतिहासिक निर्णय नारी-भविष्य की तस्वीर बदल देगा। वर्तमान में लोकसभा के कुल 543 सदस्य हैं। वर्तमान में मौजूद सदन में महिलाएं 82 हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रभावी होने के बाद 181 महिला सांसद होगी। यह अंतर आंकड़ों भर का नहीं होगा अपितु यह अंतर एक सशक्त देश की तस्वीर उकेरेगा। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न के दाग 2023 के अध्याय को कलंकित करते हैं, परंतु राहत की बात यह है कि केंद्रीय गृहमंत्री ने हाल ही में न्याय

प्रणाली में सुधार के लिए 'भारतीय न्याय संहिता 2023' सहित तीन विधेयक पेश किए। भारतीय न्याय संहिता 2023 सन् 1860 की पुरानी दंड संहिता की जगह लेगी। भारतीय न्याय संहिता 2023 की प्रमुख शक्तियों में से एक महिला के विरुद्ध अपराधों से संबंधित प्रावधानों को दी गई प्राथमिकता में निहित है। महिला उत्पीड़न पर कड़ी सजा का प्रावधान विश्वास दिलाता है कि महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों पर लगाम लगेगी। पिछले साल का अंत राहुल गांधी की 'भारत-जोड़ो यात्रा' के दिल्ली पड़ाव के साथ हुआ था और इस साल उस यात्रा का फलितार्थ था 26 प्रमुख विरोधी दलों ने 18 जुलाई को बेंगलुरु में 'नए गठबंधन इंडिया' की बुनियाद रखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाना। राहुल गांधी के लोकसभा से अयोग्य घोषित होने और उनकी बहाली और संसद के शीत सत्र में 146 सांसदों के निलंबन ने संसदीय राजनीति से जुड़े कुछ गंभीर सवालों की ओर इशारा किया है।

हिंसा, आतंक एवं युद्ध की स्थितियों के बीच भारत ने सांस्कृतिक एवं धार्मिक उत्थान एवं उन्नयन की अपूर्व परिवेश भी निर्मित किया गया, भारत के गौरव को पुनःस्थापित करने की अनूठी पहल हुई है। पांच सौ वर्षों के बाद अयोध्या में श्रीराम नये वर्ष के प्रारंभ में टेंट से मंदिर में स्थापित होंगे। वाराणसी में विश्वनाथ धाम परिसर का लोकार्पण भारत की राजनीतिक सोच को एक नया आयाम एवं दृष्टि देने का विशिष्ट उपक्रम कहा जा सकता है। हमारे देश की धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराएँ और आदर्श जीवन-मूल्य समृद्ध एवं सुदृढ़ रहे हैं, लेकिन पूर्व सरकारों ने उनके गौरव को राजनीतिक नजरिया देते हुए धूमिल किया है। लेकिन नये राजनीतिक सोच एवं सत्ता ने भारत को अपने सांस्कृतिक एवं धार्मिक वैभव से दुनिया को आकर्षित किया है, जो बीत वर्ष की सुखद घटनाएं कही जा सकती हैं। निश्चित रूप से काशी एवं अयोध्या राष्ट्रीयता का प्रतीक बनकर ये सशक्त भारत का आधार बनेगे। इससे न सिर्फ वहां जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी, बल्कि संकीर्ण दायरों में सिकुड़ते गए एक आस्था और सभ्यता के प्रतीक को भी गरिमा प्राप्त होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी, जिसे हटाए जाने का फैसला पूरी तरह संवैधानिक है। इस निर्णय ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाए जाने के 5 अगस्त, 2019 के फैसले पर कानूनी मुहर लगा दी। वैश्विक राजनीति में भारत के हस्तक्षेप की दृष्टि से दिल्ली में हुए जी-20 और शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

काशी परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भव्य एवं शालीन तरीके से करते हुए प्रत्येक भारत को स्व-आस्था, स्व-संस्कृति एवं स्व-अस्तित्व का अहसास कराया है। भारत का सांस्कृतिक वैभव दुनिया में बेजोड़ रहा है, लेकिन तथाकथित राजनीतिक स्वार्थों एवं संकीर्णताओं के चलते इस वैभव को दुनिया के सामने लाने की बजाय उसे विस्मृत करने की कुचेष्टाएं एवं षड़यंत्र लगातार होते रहे हैं। सुखद स्थिति है कि अब हमारी जागती आंखो से देखे गये स्वप्नों को आकार देने का विश्वास जागा है तो इससे जीवन मूल्यों एवं सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित करने एवं नया भारत निर्मित करने का माहौल एवं मंशा देखने को मिल रही है, जो नये वर्ष के लिये शुभ है, नये एवं समृद्ध भारत के अभ्युदय का द्योतक है।

बीते साल ने दुःख एवं निराशा के दृश्य भी दिये हैं। हिमाचल प्रदेश की बाढ़, सिलक्यारा सुरंग, बालेश्वर (बालासोर) ट्रेन-दुर्घटना, मणिपुर की हिंसा और उसके दौरान वायरल हुए शर्मनाक वीडियो से जुड़ी निराशाओं को भी भुलाना नहीं चाहिए। गत 13 दिसंबर को संसद भवन हमले की सालगिरह पर शीतकालीन सत्र के दौरान कुछ लोग अंदर कूद गए और उन्होंने एक कैन से पीले रंग का धुआं छोड़ा। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सरेआम गोली मारकर हत्या की खबर ने इस साल काफी सुर्खियां बटोरी। अप्रैल के महीने में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को एक महीने तक लगातार पीछा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।

बीता वर्ष का हर दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई एवं जुझारू व्यक्तित्व एवं नीतियों के नाम रहा। उन्ही के कारण विश्व में भारत के लिये एक नया नजरिया विकसित हुआ। उनके नाम पर लड़े गये विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हुई। तीनों राज्यों में भाजपा की सफलता के पीछे अनेक कारण हैं। मजबूत नेतृत्व, संगठन-क्षमता, संसाधन, सांस्कृतिक आधार और कल्याणकारी योजनाएं वगैरह-वगैरह। 'जो आज तक नहीं हुआ वह आगे कभी नहीं होगा' इस बूढ़े तर्क से बचकर भारत में नया प्रण जगायें। बिना किसी को मिटाये निर्माण की नई रेखाएं खींचें। यही साहसी सफर शक्ति, समय और श्रम को नये वर्ष में सार्थकता देगा।

किसी ने चंद्रयान उतारा तो किसी ने बिना हाथ जीते पदक

महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। खेल, राजनीति, सिनेमा, उद्योग कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं अपना लोहा न मनवा रही हों। जब देश ने चार साल की अधूरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर उतारा तो उसमें भी महिलाओं ने योगदान दिया। खेलों में चाहे एशियन गेम्स हों या अन्य प्रतिस्पर्धाएं वहां भी महिलाओं ने भारतीय तिरंगे को गर्व से ऊंचा उठाया है।

शीतल देवी= हाथ नहीं फिर भी दुनियाभर में दिखाया दम- शीतल एशियाई पैरा गेम्स 2023 में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हैं। वह जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ के लोइधर गांव की रहने वाली हैं। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली 16 साल की शीतल देवी का सफर हर व्यक्ति को प्रेरणा देने वाला है। वह दुनिया की पहली महिला तीरंदाज हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं। वह कंधे और मुंह की मदद से तीर चलाती हैं और दिग्गजों को पीछे छोड़ देती हैं। शीतल फोनकोमेलिया नाम की बीमार के साथ दुनिया में आईं। फोनकोमेलिया एक दुर्लभ जन्मजात बीमारी है जिसमें हाथ या पैर अविकसित रह जाते हैं। शीतल के खेल में आने की कहानी भी दिलचस्प है। जब कुछ स्थानीय प्रशिक्षकों को लगा कि वह खेलों में अच्छा कर सकती हैं, तो उन्होंने उसे कृत्रिम हाथ दिलाने की कोशिश की, लेकिन वह फिट नहीं हुआ। शीतल ने हार मानने की बजाय और भी जोर लगा दिया। ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों में वह धनुष तक नहीं उठा पाती थीं, लेकिन उन्होंने दाएं पैर से धनुष उठाने का अभ्यास किया और दो साल की कड़ी ट्रेनिंग के बदौलत जीत का परचम लहराया।

सावित्री जिंदल- कभी कॉलेज नहीं गई, आज देश की सबसे अमीर महिला- इस साल अर्थजगत में महिला उद्योगपति सावित्री जिंदल का नाम खूब चर्चा में रहा। सावित्री भारत की सबसे अमीर महिला हैं, जो वर्तमान में जिंदल ग्रुप की अध्यक्ष हैं। इस साल मध्य दिसंबर में दौलत के मामले में वह विप्रो के मालिक अजीम प्रेमजी से आगे निकलते हुए सातवें नंबर से पांचवें नंबर पर आ गई थीं। सावित्री फिलहाल छठें स्थान पर हैं। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के अनुसार, सावित्री की कुल संपत्ति 24.7 अरब डॉलर है। पिछले दो साल में ही उनकी दौलत में भारी इजाफा हुआ। असम के तिनसुकिया में 20 मार्च 1950 को सावित्री जिंदल का जन्म हुआ था। उनका विवाह 1970 में जिंदल ग्रुप के संस्थापक ओमप्रकाश जिंदल से हुआ था। उनके 9 बच्चे हैं। जब वे 55 साल की थीं, तब हेलिकॉप्टर दुर्घटना में उनके पति की मौत हो गई थी। ओम प्रकाश जिंदल हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे थे। पति की मौत के बाद उन्होंने पूरा कारोबार संभाला।

इशिता किशोर- दो बार प्री में ही फेल हुई, तीसरी बार यूपीएससी परीक्षा में किया टॉप- संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा एक सपना होता है। यह सपना कुछेक का पूरा होता है, बहुतों का नहीं। मूलरूप से पटना निवासी इशिता ने सिविल सर्विसेज परीक्षा में देश में पहले नंबर पर आकर इस सपने को जिया। दो बार संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा देने के बाद प्रीलिम्स से आगे नहीं बढ़ पाई इशिता ने हार नहीं मानी और निराशा को पीछे छोड़ते हुए 2021-2022 की परीक्षा में देश में टॉप किया। इशिता ने दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से प्राथमिक शिक्षा ली है। इशिता के पिता विंग कमांडर संजय किशोर इंडियन एयरफोर्स में थे। वर्ष 2004 में उनका देहांत हो गया था। इशिता बताती हैं कि वह सिविल सर्विसेज के जरिए देश सेवा में आना चाहती थीं। शुरू से ही वह बेहद मेहनती विद्यार्थी रही हैं। 10वीं में 90 फीसदी से अधिक अंक और 12वीं में 97 फीसदी अंक हासिल किए।

डॉ. ऋतु करिधाल श्रीवास्तव- चंद्रयान को चंद्रमा पर उतारने वाली रॉकेट वुमेन- 23 अगस्त को भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतिहास रच दिया। चंद्रयान-3 दुनिया का पहला ऐसा मिशन बन गया जो चांद की दक्षिणी सतह पर उतरा। पहली बार इस मिशन की कमान दो महिलाओं के हाथ में दी गई थी। लखनऊ की रहने वाली ऋतु को मिशन निदेशक बनाया गया था, जिनकी पहचान देश में रॉकेट वुमेन की है। चंद्रयान-3 की लैंडिंग की जिम्मेदारी इस बार वरिष्ठ महिला वैज्ञानिक डॉ. ऋतु को सौंपी गई थी। इसके पहले ऋतु मंगलयान की डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर और चंद्रयान-2 में मिशन डायरेक्टर रह चुकी हैं। ऋतु का जन्म 1975 में लखनऊ के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। बचपन से उन्हें चांद-सितारों और आसमान में दिलचस्पी थी। इसरो और नासा से संबंधित समाचार पत्रों के लेख, जानकारी और तस्वीरें इकट्ठा करना उनका शौक था।

शिवा चौहान- सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी - रक्षा क्षेत्र में कैप्टन शिवा चौहान ने इस साल खूब सुर्खियां बटोरीं। जनवरी में शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं। राजस्थान की रहने वाली शिवा एक बंगाल सैपर अधिकारी हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा उदयपुर से पूरी की है और एनजेआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उदयपुर से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। 11 साल की छोटी उम्र में शिवा के सिर से पिता का साया उठ गया था। मां ने शिवा की पढ़ाई का ध्यान रखा और बचपन से ही, उन्हें भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। मई 2021 में शिवा को इंजीनियर रेजिमेंट में नियुक्त किया गया।

निर्मला सीतारमण- दिसंबर की शुरुआत में फोर्ब्स की ओर से विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई थी। इस सूची में तीन भारतीय महिलाओं के भी नाम थे जिसमें देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हैं। यह पांचवी बार है जब उनका नाम इस सूची में है। निर्मला सीतारमण को इस बार 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 32वां स्थान मिला। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और भू-राजनीतिक जोखिमों के बावजूद भारत ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अच्छा किया है। जहां वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में 7.7% की मजबूत जीडीपी वृद्धि हासिल की तो, वहीं औद्योगिक गतिविधि में लगातार वृद्धि देखी गई। भारत का दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से है।

किरण मजूमदार-शॉ- फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची लिस्ट में किरण मजूमदार-शॉ भी शामिल हैं। किरण को 76वें स्थान पर जगह मिली है। किरण मजूमदार शॉ भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड बायोफार्मास्युटिकल कंपनी बायोकॉन की फाउंडर हैं। ये दवा उत्पादन के क्षेत्र की बड़ी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 1978 में हुई थी। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

रोशनी नादर मल्होत्रा- रोशनी को फोर्ब्स की ओर से जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। रोशनी नाडर मल्होत्रा को 60वें स्थान पर जगह मिली है। रोशनी दिग्गज टेक कंपनी एचसीएल की सीईओ हैं। वह एचसीएल के संस्थापक शिव नाडर की एकलौती बेटी हैं। रोशनी नाडर 2020 में देश की सबसे अमीर महिला भी बनी थीं। कंपनी के रणनीतिक फैसलों में शुरू से ही बड़ी भूमिका निभाने वाली रोशनी को महज 28 साल की उम्र में सीईओ बनाया गया था। एक साल बाद ही कॉरपोरेशन की कार्यकारी निदेशक बन गई। फोर्ब्स ने 2017-2018 और 2019 में भी उन्हें दुनिया की 100 ताकतवर महिलाओं में शुमार किया था।

नीता अंबानी- नीता रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन हैं। इसी साल अक्टूबर में उन्हें यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने नीता अंबानी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया था। नीता अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। वह मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क के ट्रस्टी बोर्ड में शामिल होने वाली पहली भारतीय भी हैं। बच्चों आकाश, ईशा और अनंत को आगे बढ़ाने के लिए इसी साल ऋहुरु के बोर्ड से नीता अंबानी ने इस्तीफा दिया था। आकाश, ईशा और अनंत गैर-कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए थे।

काश्वी गौतम- पारी में सभी 10 विकेट लेकर मचाई थी सनसनी - महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन में काश्वी गौतम पर दो करोड़ की बोली लगी है। काश्वी का बेस प्राइस 10 लाख रुपये था और उन्हें 20 गुना ज्यादा कीमत पर गुजरात जाएंट्स ने अपने साथ जोड़ा। दाएं हाथ से बेहतरीन तेज गेंदबाजी करने के साथ ही काश्वी बड़े शॉट खेलने में भी माहिर हैं।

उन्होंने 2020 में महिलाओं की घरेलू अंडर-19 प्रतियोगिता में चंडीगढ़ के लिए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ वनडे मैच में हैट्रिक सहित दस विकेट लिए। इसके साथ ही उन्होंने खास कीर्तिमान अपने नाम किया था। इसी वजह से वह सभी फ्रेंचाइजी की नजरों में बनी हुई थीं।

बच्चे के फोन एडिक्ट होने की वजह आप खुद, जानिए कैसे?

पहले जमाने में जहां बच्चे खिलौने से खेलना पसंद करते थे आज वहीं बदलते समय और तकनीक के साथ बच्चों के हाथों में मोबाइल की जगह फोन दिख रहे हैं। स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप जैसी चीजों के बच्चे इतने ज्यादा आदि हो गए हैं कि इसके कारण उन्हें मोटापा, डिप्रेशन, कमजोर आईसाइट जैसी समस्याएं हो रही हैं। हालांकि इन सभी में बच्चों के साथ-साथ कहीं न कहीं पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों से ही कई सारी बातें सीखते और करते हैं। आज आपको कुछ ऐसी गलतियां बताते हैं जिनके कारण आपके बच्चे फोन के आदि हो रहे हैं।

ज्यादा फोन इस्तेमाल करना

यदि आप खुद फोन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों को फोन से कैसे दूर रख सकते हैं। क्योंकि आपको देखकर ही बच्चे अच्छी और बुरी आदतें सीखेंगे। यदि आप खुद सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं या फिर बच्चों के सामने फोन का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि बच्चे फोन से दूर रहे हैं तो उन्हें फोन देने का एक समय रखें। जब बच्चे आपके आस-पास हों तो उन्हें समय दें और फोन को एक तरफ रख दें।

खुद फोन दे देना

एक्सपर्ट्स की मानें तो बच्चे को किसी भी चीज से दूर रखने के लिए उसे लालच देना ठीक नहीं है। हालांकि ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों को कंट्रोल रखने के लिए यही तरीका आजमाते हैं। पेरेंट्स बच्चों की जिद्द पूरी करने के लिए उन्हें फोन चलाने के लिए दे देते हैं। हालांकि बच्चे आगे चलकर जिद्दी बन जाते हैं और बात भी नहीं मानते। इसलिए यदि उन्हें स्क्रीन से होने वाले नुकसान के बारे में बताएं। अपनी बात मनवाने के लिए बच्चों को लालच बिल्कुल भी न दें। ज्यादा स्क्रीन पर समय बिताने के कारण बच्चों पर बुरा असर हो सकता है।

बच्चे को एक्टिविटीज न करवाना

पेरेंट्स बच्चों के बोर होने पर उन्हें हाथ में फोन पकड़ा देते हैं या फिर टीवी चला देते हैं लेकिन यह आदत सही नहीं है इसके कारण बच्चों की आंखों पर बुरा असर पड़ता है। फोन की जगह आप बच्चे से इंडोर एक्टिविटीज करवाएं। इसके अलावा आप चाहें तो बच्चों को ऐसी मेमोरी गेम्स करवा सकते हैं जिससे उनका दिमाग विकसित हो।

बच्चों को समय न दे पाना

जब पेरेंट्स बच्चों को समय न दें तो भी वह अपना समय बिताने के लिए तरीका ढूंढ लेते हैं। लेकिन सही परवरिश वही है जिसमें आप बच्चों को समय दें। ये अच्छी परवरिश की तरफ ही पहला कदम होता है। बच्चों को यदि आप समय नहीं देंगे तो वह ऐसी आदतों के शिकार हो जाएंगे जो उनके लिए हानिकारक हो सकती हैं। पेरेंट्स के समय न देने के कारण ही बच्चे मोबाइल फोन के आदि हो सकते हैं।

पति-पत्नी के रिश्ते को तोड़ सकती हैं ये छोटी-छोटी गलतियां, समय रहते दें इन पर ध्यान

मनमुटाव हर रिश्ते में होते हैं। लेकिन अगर इनपर ध्यान न दिया जाए तो ये रिश्ते में दरार पैदा कर देते हैं। इन सबके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जो पति-पत्नी के बीच दूरियां पैदा करती है। इन चीजों पर ध्यान दें ताकि बाद में पछतावा न पड़ें।

रिश्ता कोई भी हो आपको उस पर काम करना पड़ता है। लेकिन बाद जब शादीशुदा रिश्ते की आती है तब मेहनत थोड़ी बढ़ जाती है। दरअसल, शादीशुदा रिश्ते में लोगों को अपने साथ-साथ अपने पार्टनर की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। कई बार इन जिम्मेदारियों की वजह से पति-पत्नी में मनमुटाव भी हो जाते हैं। वैसे मनमुटाव हर रिश्ते में होते हैं। लेकिन अगर इनपर ध्यान न दिया जाए तो ये रिश्ते में दरार पैदा कर देते हैं। इन सबके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जो पति-पत्नी के बीच दूरियां पैदा करती है। इन चीजों पर ध्यान दें ताकि बाद में पछतावा न पड़ें।

जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रखना- हर किसी को अपने पार्टनर से कुछ उम्मीदें होती है। इन उम्मीदों को पूरा करना हमारे पार्टनर का फर्ज होता है। लेकिन कई बार हम अपने पार्टनर से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं और जब वह उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो हमारे बीच मनमुटाव हो जाता है। इसकी वजह से रिश्ते में दूरियां भी आ जाती है। इसलिए लोगों को पार्टनर से जरुरत से ज्यादा उम्मीदें नहीं करने की सलाह दी जाती है।

अपने आप को सही ठहराना- पति-पत्नी में छोटी-छोटी बातों पर बहस होती रहती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इन बहस में पति और पत्नी के बीच खुद को सही ठहराने की होड़ लग जाती है और फिर बात बढ़ जाती है। खुद को सही ठहराने की होड़ में अक्सर लोग अपना रिश्ता ख़राब कर लेते हैं, जो ठीक नहीं है। पति-पत्नी को ऐसा करने से बचना चाहिए।

एक-दूसरे को नजरअंदाज करना- बहस के बाद पति-पत्नी मुद्दे को सुलझाने की बजाय एक दूसरे को नजरअंदाज करने लगते हैं। अगर दोनों में से एक भी बात करने की कोशिश करता है तो दूसरा उसकी बात को टाल देता है। ऐसा करने से रिश्ते की नींव कमजोर हो जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि एक-दूसरे से बातचीत करें और मुद्दे को सुलझाएं।

सर्दियों में Parents ऐसे करें बच्चों की मालिश, हड्डियां बनेगी मजबूत

ठंड का मौसम शुरु हो चुका है ऐसे में इस दौरान बच्चे के लिए तेल मालिश बहुत ही फायदमंद होती है। कम उम्र में बच्चे की हड्डियों का विकास हो रहा है होता है। यदि इस दौरान पेरेंट्स बच्चों की मालिश करें तो यह मजबूत बनेगी। इस मौसम में बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ों के मुकाबले कमजोर होती है जिसके कारण वह जल्दी बीमार हो जाते हैं। बच्चों की मालिश करने से उनका शरीर मजबूत बनेगा।

मालिश से बच्चों को होने वाले फायदे

- सर्दियों में तेल मालिश करने से बच्चे की मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत बनेगी।
- ठंड के दिनों में तेल से मालिश करने से बच्चे को नींद अच्छी आएगी ।
- तेल मालिश से बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और उसकी ग्रोथ होगी।
- रोजाना तेल मालिश से बच्चे को सर्दी-जुकाम जैसी समस्या से भी राहत मिलती है।
- इसके अलावा पेट संबंधी समस्याओंसे भी बच्चों को आराम मिलता है।

कैसे करें बच्चों की मालिश?

- मालिश के लिए सबसे पहले बच्चे के पैर से शुरुआत करें। हाथों को शिशु के पैर पर लंबा लेकर जाएं फिर गोल-गोल घुमाते हुए उसकी मालिश कर लें।
- मालिश के समय हाथों को पहले आप ऊपर लेकर जाएं और फिर नीचे लेकर जाएं। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा।
- मालिश के लिए आप हाथों और उंगलियों का इस्तेमाल ध्यान से करें।
- इस दौरान हल्की स्ट्रेचिंग भी जरुरी है। शिशु के पैर को हल्का स्ट्रेच करें।
- हाथों को भी हल्का स्ट्रेच करें और फिर मालिश करें।
- इसके बाद पेट, गर्दन और पीठ पर उंगलियों के जरिए मालिश करें।

. इन हिस्सों में स्ट्रेचिंग की जरुरत आपको नहीं पड़ेगी, सिर्फ उंगलियों के जरिए ही मालिश करना बच्चे के लिए लाभकारी होता है।

इस बात का भी रखें ध्यान

- बच्चे की त्वचा के लिए नारियल तेल, सरसों का तेल या फिर तिल का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
- बच्चे की त्वचा के लिए सर्दी के दिनों में आप गुनगुना तेल ही इस्तेमाल करें। इस बात का ध्यान रखें कि शिशु की त्वचा पर ज्यादा गर्म तेल बिल्कुल भी न लगाएं।

- मालिश करने के लिए तेल की कुछ बूंदे अपनी हथेली पर डालें और दोनों हाथों के बीच में लगाएं। इसके बाद शिशु की मालिश करें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

विपक्षी गठबंधन के नेता सीईसी के साथ करना चाहते हैं बैठक

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा है। इस पत्र में जयराम रमेश ने बताया है कि वीवीपैट को लेकर विपक्षी गठबंधन के नेता कुछ सुझाव देना चाहते हैं, इसके लिए वह मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलना चाहते हैं। पत्र में चुनाव आयुक्त से बैठक के लिए समय देने की मांग की गई है। पत्र में जयराम रमेश ने लिखा कि बीती 20 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें वीवीपैट के इस्तेमाल को लेकर कुछ सुझाव दिए गए। विपक्षी गठबंधन की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया, अब इसे लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलना चाहते हैं। जयराम रमेश ने बताया कि हम बैठक में पास किए गए प्रस्ताव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलना चाहते हैं लेकिन अभी तक हम इसमें सफल नहीं हो पाए हैं। मैं एक बार फिर विनती करता हूं कि इंडिया गठबंधन के 3-4 सदस्यों की टीम को चुनाव आयुक्तों से मिलने का अवसर दिया जाए ताकि हम वीवीपैट पर अपने सुझाव दे सकें।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी दफ्तर पहुंचे कार्ति चिदंबरम

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे। सूत्रों के अनुसार साल 2011 में चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कार्ति चिदंबरम को इस मामले में आखिरी बार पिछले साल 23 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। केंद्रीय एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो की एफआईआर के अनुसार, यह मामला वेदांत ग्रुप कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के एक शीर्ष अधिकारी द्वारा कार्ति और उनके सहयोगियों को रिश्वत के तौर पर 50 लाख रुपये देने का है। सीबीआई के अनुसार, पावर प्रोजेक्ट का काम चीनी कंपनी द्वारा किया जा रहा था, लेकिन काम निर्धारित समय से पीछे चल रहा था। टीएसपीएल के एक कार्यकारी ने 263 चीनी श्रमिकों के लिए प्रोजेक्ट वीजा फिर से जारी करने की मांग की थी, जिसके लिए 50 लाख रुपये का आदान प्रदान किया गया था।

जगन मोहन की बहन 4 को कांग्रेस में हो सकती हैं शामिल

अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला के 4 जनवरी को कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। वाईएस शर्मिला वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। यह घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी द्वारा तेलंगाना में विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने और राज्य में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) का प्रभुत्व खत्म करने के कुछ दिनों बाद आया है। इस बीच वाईएस शर्मिला ने आज सुबह 11 बजे पार्टी के सभी नेताओं के साथ बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के विलय और भविष्य की गतिविधियों पर चर्चा होने की संभावना है। तेलंगाना में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले वाईएस शर्मिला ने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना समर्थन दोहराया था। उन्होंने वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाला चुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया है, जिससे तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव को फायदा हो सकता था।

एकनाथ शिंदे 6 जनवरी से शुरू करेंगे शिव संकल्प अभियान

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे अपने शिव संकल्प अभियान के एक हिस्से के रूप में राज्य भर की सभी 48 लोकसभा सीटों पर रैलियों के साथ महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बजाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, भले ही उनकी पार्टी का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अभियान के अलावा शिंदे अपने गठबंधन सहयोगियों भाजपा और अजित पवार की एनसीपी के साथ भी अभियान के तहत संयुक्त रैलियां करेंगे। अभियान की योजना और तैयारी की निगरानी के लिए शिवसेना ने एक केंद्रीय समिति का गठन किया है। पैनल अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी जिलों में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ समन्वय करेगा। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन की संयुक्त रैलियों से पहले शिंदे की रैलियां दो चरणों में होंगी। पहला चरण 6 जनवरी को विदर्भ क्षेत्र के यवतमाल में एक रैली के साथ शुरू होगा और छत्रपति संभाजीनगर में एक रैली के साथ समाप्त होगा।

ईडी की रडार पर हेमंत सोरेन अब पत्नी चलाएगी सरकार?

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से छह समन अब तक मिल चुके हैं। लेकिन हरेक बार उन्होंने अनुपस्थित होकर प्रवर्तन निदेशालय को अन्य विकल्प तलाशने की ओर मोड़ दिया है। ऐसे में कहा ये भी जा रहा है कि हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसी क्रम में राज्य में एक अन्य घटनाक्रम भी देखने को मिला है। प्रदेश की गांडेय विधानसभा सीट से विधायक सरफराज अहमद ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। अहमद के पिछले कई दिनों से विधायक पद छोड़ने की खबरें आ रही थी। विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र महतो ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। उनके इस्तीफे के बाद झारखंड विधानसभा में 31 दिसंबर 2023 से पद रिक्त हो गया है। पूरे प्रकरण पर गोंडा से बीजेपी सांसद निशिकांत दूबे ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। झारखंड की अगली मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन होंगी।

तमिलनाडु भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब : मोदी

प्रधानमंत्री बोले- आने वाले 25 साल विकसित राष्ट्र बनाने के हैं

चेन्नई। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार से दो दिवसीय दक्षिण दौरे पर तिरुचिरापल्ली पहुंचे। दौरे के तहत पीएम मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भारतीदासन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इसके साथ उन्होंने तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तिरुचिरापल्ली में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा साल 2004-2014 के बीच केंद्र से तमिलनाडु को 30 लाख करोड़ रुपये मिले थे लेकिन हमारी सरकार ने बीते 10 सालों में तमिलनाडु को 120 लाख करोड़ रुपये दिए हैं। हमने तमिलनाडु सरकार को ढाई गुना ज्यादा पैसा दिया है। पीएम मोदी ने कहा बीते एक साल में 40 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री 400 से ज्यादा बार तमिलनाडु आए हैं। जब तमिलनाडु तेजी से प्रगति करेगा तो देश भी तेजी से विकास करेगा।

तिरुचिरापल्ली की भारतीदासन यूनिवर्सिटी के 38वें दीक्षांत समारोह में दिए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा जो विज्ञान आप सीख रहे हैं, वह एक गांव के किसान की मदद कर सकता है, कई जटिल समस्याओं का समाधान कर सकता है। जो बिजनेस मैनेजमेंट आप सीख रहे हैं, वह उद्योगों की मदद कर सकता है और लोगों की कमाई बढ़ा सकता है। जो अर्थशास्त्र आप सीख रहे हैं, वह गरीबी घटा सकता है। इस तरह जो भी यहां से स्नातक हो रहा है, वह 2047 में विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दे सकता है।

इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं कामना करता हूं कि वर्ष 2024 सभी के लिए शांतिपूर्ण और समृद्ध हो। यह सौभाग्य की बात है कि 2024 में मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम तमिलनाडु में हो रहा है। आज लगभग 20,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं तमिलनाडु की प्रगति को मजबूत करेंगी। मैं आपको इन परियोजनाओं के लिए

बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाएं तमिलनाडु की प्रगति को मजबूत करेंगी। मैं आपको इस परियोजना के लिए बधाई देता हूं जिसमें रेलवे, सड़क मार्ग, बंदरगाह, हवाई अड्डे, ऊर्जा और पेट्रोलियम पाइपलाइन शामिल हैं।

मोदी ने कहा कि 2023 के आखिरी कुछ हफ्ते तमिलनाडु के कई लोगों के लिए मुश्किल भरे रहे। भारी बारिश के कारण हमने अपने कई साथी नागरिकों को खो दिया। संपत्ति का भी काफी नुकसान हुआ है। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार तमिलनाडु के लोगों के साथ खड़ी है। हम राज्य सरकार को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के हैं। जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं, तो इसमें आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों पहलू शामिल हैं। इसलिए मैं इसमें तमिलनाडु की विशेष भूमिका देखता हूं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। तमिलनाडु के पास तमिल भाषा और ज्ञान का प्राचीन खजाना है। संत तिरुवल्लुवर से लेकर सुब्रमण्यम भारती तक अनेक संतों ने अद्भुत साहित्य की रचना की है। सीवी रमण से लेकर आज तक अनेकों अद्भुत सांइस्टिफिक और टेक्नोलाजिकल ब्रेन इस मिट्टी ने पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले हमने श्री तिरु विजयकांत जी को खो दिया। वह न केवल सिनेमा की दुनिया में बल्कि राजनीति में भी एक कप्तान थे। उन्होंने फिल्मों में अपने काम से लोगों का दिल जीता। एक राजनेता के रूप में उन्होंने सदैव राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।

मोदी ने कहा कि आज मैं तमिलनाडु के एक और सपूत डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन जी को भी याद कर रहा हूं, जिन्होंने हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास है कि देश के विकास और विरासत में तमिलनाडु से मिली सांस्कृतिक प्रेरणा का लगातार विस्तार हो। आपने देखा है कि दिल्ली में संसद के नए भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। ये गुड गवर्नेंस की उस मॉडल से प्रेरणा लेने का प्रयास है, जो तमिल परंपरा ने पूरे देश को दिया है। उन्होंने कहा कि तिरुचिरापल्ली में, हम पल्लव, चोल, पांडे और अन्य जैसे विभिन्न राज्यों के सुशासन मॉडल देखते हैं। मैं जहां भी जाता हूं, तमिलनाडु की समृद्ध विरासत को दुनिया के सामने दिखाने का लगातार प्रयास करता हूं।

टर्मिनल बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि एयरपोर्ट सिर्फ यात्रा का माध्यम ना रहें बल्कि एयरपोर्ट ग्रोथ का केंद्र बनें। आज एयरपोर्ट देश में रोजगार का केंद्र बने हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल में जो बदलाव हुआ है, उसमें हवाई यात्रा को सभी के लिए सुलभ बनाया गया है। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम स्टालिन, राज्यपाल आरएन रवि और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे।

इंडिया गठबंधन की हो सकती है आज वर्चुअल बैठक

नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की संभावना

नईदिल्ली। जद (यू) प्रमुख के विपक्षी गुट से नाराज होने की अटकलों के बीच, इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं और बिहार के मुख्यमंत्री के बीच मंगलवार (3 जनवरी) को वस्तुत: चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गठबंधन में कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उन्हें विपक्षी गुट का संयोजक बनाने का प्रस्ताव दे सकते हैं। जूम ऐप पर चर्चा में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई शीर्ष नेता हिस्सा लेंगे। इस दौरान इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के भी शामिल होने की संभावना है।

सूत्रों के मुताबिक इस मामले को लेकर कांग्रेस ने राजद नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव से भी सहमति ले ली है। उन्होंने कहा, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी चर्चा हो चुकी है। नई दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरें सामने आने लगीं। कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री पद के लिए कुमार का नाम प्रस्तावित किया जाना था, लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया, जिससे जेडीयू प्रमुख नाराज हो गए। कुमार के अलावा राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी मुलाकात के बाद खुश नहीं दिखे। 19 दिसंबर को विपक्षी गुट की चौथी बैठक राष्ट्रीय राजधानी में हुई और इसमें 28 दलों के नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा कि सीट-बंटवारे की बातचीत बिना किसी देरी के शुरू होनी चाहिए और संयुक्त रैलियों का भी प्रस्ताव है। कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन ने आगामी आम चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को एक संयुक्त चुनौती देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ आकार लिया। संयुक्त विपक्ष की पहली बैठक 23

जून को पटना में और दूसरी बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई. तीसरी बैठक 31 अगस्त-1 सितंबर को मुंबई में हुई।

इंडिया गठबंधन में फूट!

नईदिल्ली। कांग्रेस ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक थी कांग्रेस वाले तंज एक था जोकर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी (आप) और पीएम मोदी के सपने इतने समान हैं क्योंकि वे दोनों कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। पूर्व ट्विटर एक्स पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, आप और मोदी के विचार कितने समान हैं! ये दोनों कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखते हैं... वैसे, एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर। आपने देखी होगी? पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया तब आई है जब सीएम भवंत मान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, पंजाब और दिल्ली में, मां अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुना सकती हैं - एक थी कांग्रेस। जब उनसे इंडिया के बीच सीट समायोजन के मुद्दे के बारे में पूछा गया, ब्लॉक पार्टनर्स, मान ने कहा कि इन मामलों पर गठबंधन की बैठक में चर्चा की जाएगी और कहा, चीजों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही हम बता पाएंगे।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज

जोहानिसबर्ग। पहले टेस्ट में शर्मनाक हार के बाद वापसी के लिये भारतीय गेंदबाजों को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यहां बुधवार से शुरू हो रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन करना होगा ताकि विश्व चैम्पियनशिप अंक तालिका में ऊपर आने का रास्ता बन सके। इस समय विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप 2023-25 चक्र में दक्षिण अफ्रीका शीर्ष पर है जबकि भारत छठे स्थान पर है। हरफनमौला रविंद्र जडेजा की वापसी से मध्यक्रम संतुलित होगा और बीच के ओवरों में पुरानी कूकाबूरा से वह प्रभावी साबित होंगे। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10.30 बजे शुरू होगा।

भारत के लिये तीसरे और चौथे तेज गेंदबाज की भूमिका अहम होगी। प्रसिद्ध कृष्णा अभी टेस्ट क्रिकेट के लिये तैयार नहीं हैं और शार्दुल ठाकुर लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं । बल्लेबाजों में शीर्ष तीन यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के खराब फॉर्म ने टीम की चिंता बढा दी है । उन्हें दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के बाउंसर झेलने होंगे। पहले टेस्ट की पहली पारी में केएल राहुल और दूसरी पारी में विराट कोहली को छोड़कर भारत का कोई बल्लेबाज सेंचुरियन में अतिरिक्त उछाल का सामना नहीं कर सका । नये विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप चक्र में एक हार और एक ड्रॉ के बाद भारत जीत के लिये बेताब होगा । इस मैदान पर हालांकि पिछले छह में से चार मैच भारत गंवा चुका है। पिछले छह सप्ताह कप्तान रोहित शर्मा के लिये अच्छे नहीं रहे हैं जो वनडे विश्व कप फाइनल की हार के बाद उबरने की कोशिश कर रहे हैं । इसके बाद सेंचुरियन में ढाई दिन के भीतर टेस्ट में पारी और 32 रन के अंतर से हार ने उनकी समस्यायें बढा दी है । अब ऐसे में नये साल की शुरूआत यहां न्यूलैंड्स पर जीत के साथ करने के लिये वह बेताब होंगे । इस मैदान पर दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी है ।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 379 अंक टूटा निफ्टी 21,700 के नीचे

नईदिल्ली। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 379 अंक फिसलकर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 82 अंक की गिरावट दर्ज की गई। व्यापक बाजारों में, बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में 0.9 प्रतिशत की गिरावट आई। व्यापक बाजारों में, बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक घाटे की भरपाई करने से पहले इंट्राडे ट्रेड में 0.5 प्रतिशत से अधिक गिर गए और नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 379.46 अंक यानी 0.53 फीसदी की गिरावट के साथ 71,892.48 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 71,613.74 और 72,332.85 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 81.65 अंक यानी 0.38 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 21,660.25 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 21,555.65 और 21,755.60 के रेंज में कारोबार हुआ।

अशोक लेलैंड की कुल बिक्री में दिसंबर में 10% की गिरावट

नईदिल्ली। हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड की कुल बिक्री दिसंबर 2023 में 10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 16,324 इकाई रही। दिसंबर 2022 में यह 18,138 इकाई थी। अशोक लेलैंड ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि घरेलू बिक्री 10 प्रतिशत घटकर 15,323 इकाई रही। दिसंबर 2022 में यह 17,112 इकाई थी। घरेलू बाजार में मध्यम तथा भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 11 प्रतिशत घटकर 10,102 इकाई रही, जो 2022 में इसी महीने में 11,399 इकाई थी। कंपनी के अनुसार, पिछले महीने घरेलू बाजार में हल्के वाणिज्यिक वाहन की बिक्री नौ प्रतिशत की गिरावट के साथ 5,221 इकाई रही, जो दिसंबर 2022 में 5,713 इकाई थी।

ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से जरूरी सामानों की आपूर्ति बंद

नईदिल्ली। देशभर में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के बाद कई राज्यों में चक्का जाम हो गया है और इस वजह से जरूरी सामानों की आपूर्ति भी थम गई है। इस हड़ताल का सबसे ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। एमपी की राजधानी भोपाल में तो बस और ट्रक के साथ-साथ टैक्सी और ट्रेक्टर भी रोक दिए गए हैं और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। साथ ही छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी कई जगहों पर ट्रक ड्राइवरों ने विरोध-प्रदर्शन निकाला है जिस वजह से फल-सब्जियों की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में नये कानून में 'हिट एंड रन' के मामलों में सख्त सजा के प्रावधानों के खिलाफ ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। इसके चलते मध्यप्रदेश में करीब पांच लाख छोटी-बड़ी गाड़ियों के चक्के थम गए हैं जिससे आम जरूरत की चीजों की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है।

लेमन ट्री होटल्स के शेयर में 10% से ज्यादा का उछाल

नईदिल्ली। लेमन ट्री होटल्स के शेयर बीएसई पर इंट्रा-डे कारोबार में 9 प्रतिशत तक बढ़कर 129.30 रुपये के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गए। कंपनी के इनकम में मजबूत वृद्धि के चलते उसके शेयरों में यह उछाल आया है। वहीं, एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स सुबह 11.30 बजे 548.60 गिरकर 71,958 पर कारोबार कर रहा था। सुबह 11.30 बजे लेमन ट्री होटल्स का शेयर 10.61 प्रतिशत या 12.60 रुपये की छलांग के साथ 131.30 रुपये के रिकॉर्ड लेवल पर करोबार कर रहा था। इस तेजी के साथ लेमन ट्री होटल्स के शेयर ने पिछले साल 15 सितंबर को 126.80 रुपये के अपने पिछले हाई लेवल को पार कर लिया। काउंटर पर औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम आज दोगुने से अधिक हो गया। लेमन ट्री होटल्स स्वामित्व और पट्टे के कमरों में रुचि को नियंत्रित करने के आधार पर भारत की सबसे बड़ी होटल चेन में से एक है।

भारत में निवेशक हुए मालामाल, अर्थव्यवस्था में जारी है उछाल

प्रह्लाद सबनानी

भारतीय शेयर (पूंजी) बाजार द्वारा वर्ष 2023 में 20 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर अर्जित की गई है। वर्ष 2023 में सेन्सेक्स 11,399 अंकों (18.73 प्रतिशत) की बढ़त के साथ 72,082 अंकों के स्तर पर बंद हुआ है तो वहीं निफ्टी 3,626 अंको (20 प्रतिशत) की बढ़त के साथ 21,731 अंकों के स्तर पर बंद हुआ है।

भारत के शेयर बाजार में उक्त वर्णित तेजी के चलते वर्ष 2023 में भारत के शेयर बाजार में निवेशकों के शेयरों में निवेश का बाजार मूल्य 81.90 लाख करोड़ रुपए से बढ़ गया है, जबकि वर्ष 2022 में यह 16.38 लाख करोड़ रुपए से बढ़ा था। यह भारत की लगातार उच्च स्तर की आर्थिक प्रगति एवं देश में राजनैतिक वातावरण के स्थिर बने रहने के कारण सम्भव हो सका है। हाल ही में तीन राज्यों में सम्पन्न हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के कारण भी शेयर बाजार में उच्छाल देखा गया था। वर्ष 2023 में बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज पर लिस्टेड कम्पनियों के शेयरों का बाजार पूंजीकरण 81.90 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ 364.28 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पर कर गया है। वर्ष 2023 में भारतीय शेयर बाजार में दर्ज की गई उक्त वृद्धि दर विश्व के समस्त इमर्जिंग बाजारों के बीच सबसे अधिक है। 29 नवम्बर 2023 को तो बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज पर पंजीकृत समस्त कम्पनियों का बाजार पूंजीकरण का स्तर 4 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया था जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार से भी अधिक है। भारत के संदर्भ में यह भी अपने आप में एक रिकार्ड है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार अभी 3.75 लाख करोड़ रुपए का ही है। 24 मार्च 2021

को बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज पर पंजीकृत समस्त कम्पनियों का बाजार पूंजीकरण 3 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचा था, इस प्रकार केवल 2 वर्ष 8 माह के खंडकाल में ही उक्त कम्पनियों द्वारा जारी शेयरों का बाजार पूंजीकरण एक लाख करोड़ रुपए की राशि से बढ़ गया है।

वर्ष 2023 में भारत के बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज के समाल केप (छोटे आकर की कम्पनियों द्वारा जारी शेयरों का बाजार पूंजीकरण) इंडेक्स में तो 47.52 प्रतिशत की बृद्धि दर आंकी गई है। वहीं, मिड केप (मध्यम आकार की कम्पनियों द्वारा जारी शेयरों का बाजार पूंजीकरण) इंडेक्स द्वारा 45.52 प्रतिशत की वृद्धि दर अर्जित कर की गई है।

30 शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज इंडेक्स ने केवल नवम्बर 2023 माह में ही 4.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और दिसम्बर 2023 माह तो 7.83 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आगे बढ़ा है। इस प्रकार नवम्बर एवं दिसम्बर 2023 माह भारत में निवेशकों के लिए बहुत फलदायी सिद्ध हुए हैं। यह सब भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2023-24 की दो तिमाहीयों, अप्रेल-जून 2023 में 7.8 प्रतिशत की एवं जुलाई-सितम्बर 2023 में 7.6 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर हासिल करने एवं कम्पनियों की लाभप्रदता में हुई अतुलनीय वृद्धि दर के चलते सम्भव हो पाया है। साथ ही, भारत में वृहद (मैक्रो) स्तर पर अर्थव्यवस्था में मजबूत संकेत बने हुए है तथा अब मुद्रा स्फीति पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भी कुछ नरमी आई है। इससे भारतीय रुपए के मूल्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमत में भी स्थिरता दिखाई दी है। आज भारत के शेयर बाजार में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों का बाजार पूंजीकरण 17.48 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया है, जो भारत में प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर टाटा कन्सल्टैंसी सर्विसेज है, जिसका शेयर बाजार पूंजीकरण 13.88 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, तृतीय स्थान पर 12.98 लाख करोड़ रुपए के शेयर बाजार पूंजीकरण के साथ एचडीएफसी बैंक है। चतुर्थ स्थान पर 6.99 लाख करोड़ रुपए के शेयर बाजार पूंजीकरण के साथ आईसीआईसीआई बैंक है। इनफोसिस कम्पनी का पांचवा स्थान है, जिसका शेयर बाजार पूंजीकरण 6.40 लाख करोड़ रुपए का है।

हिट एंड रन कानून का विरोध : बस, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल

पेट्रोल पंप पर लगी भीड़, सैकड़ों बंद

रायपुर। रायपुर के साथ ही अब दुर्ग, भिलाई में भी ईंधन की किल्लत शुरू हो गई है। वाहन चालकों की हड़ताल के चलते ईंधन की आपूर्ति रूक गई है। हड़ताल की सूचना मिलते ही नागरिक बड़ी संख्या में पेट्रोल पंपों में पहुंचने लगे हैं। पेट्रोल पंपों में सुबह से लेकर देर रात तक वाहनों की कतार ईंधन लेने लगी हुई है। वहीं थोक सब्जी मंडी में भी लगभग 75 प्रतिशत तक सप्लाई ठप हो चुकी है। वाहन चालकों ने अपने-अपने गाडियों के पहिए रोक दिए हैं, इससे सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप हो गई है। परिणाम स्वरूप आज सुबह से ही सब्जी बाजार में एक बार फिर से उछाल आ गया और हरी सब्जियों के दाम अचानक बढ़ गए। आम दिनों में थोक सब्जी मंडी में सौ से अधिक ट्रक आते थे, लेकिन सोमवार को आधे ही ट्रक आ पाए जिससे सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं। थोक के दाम में रोजाना 20 की मिर्च 40 रुपए किलो, मटर 20 की जगह 30 रुपए किलो की दर से बिका। रायपुर में महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल और गुजरात के ट्रक सब्जियां लेकर आते हैं जो नहीं आ पा रहे हैं।

जाम करने पर एफआईआर के आदेश :

अब खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से सभी कलेक्टर को आदेश जारी किया है कि जाम करने पर सीधे एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करें। छत्तीसगढ़ में सोमवार से शुरू हुई बस और ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल मंगलवार को भी जारी है। पेट्रोल की सप्लाई प्रभावित होने से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, जगदलपुर में देर रात तक पेट्रोल पंप पर भीड़ लगी रही। सब्जियों की सप्लाई रुकने से उनके दाम बढ़ गए हैं। कई स्कूलों के बस ड्राइवर भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं।

पेट्रोल पंपों में विवाद की स्थिति :

रायपुर के जीई रोड, भाटागांव स्थित पेट्रोल पंप पर विवाद के हालात बन गए। लोगों को अपनी पारी का इंतजार करते हुए आधे घंटे का वक्त लग रहा था। तब जाकर कुछ लोंगों को पेट्रोल मिल पाया। ये हड़ताल केंद्र सरकार के कानून का विरोध है जिसमें हिट एंड रन मामले में ड्राइवर्स को कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

अंतरराज्यीय बस स्टैण्ड में बसों के थमे पहिए :

रायपुर के इंटर स्टेट बस टर्मिनल में यात्री बसों के पहिए थम गए। हड़ताल के चलते कोई भी चालक बस नहीं चला रहा है। बस स्टैंड में आने वाले यात्री वापस लौट रहे हैं। ड्राइवर्स 3 जनवरी तक आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं। भिलाई दुर्ग में टैंपो आटो संचालन पर भी भारी असर देखा गया है। निजी स्कूल के बस ड्राइवरों और मैनेजमेंट का कहना है कि उनके पास केवल एक या दो दिन का पेट्रोल बचा है। जो उनकी गाडियों में डला हुआ है। आगे पेट्रोल डीजल नहीं मिला तो स्कूल बसों के पहिये थम जाएंगे।

एंबुलेंस व शासकीय वाहनों के लिए ईंधन रिजर्व :

जिन पेट्रोल पंप में पेट्रोल-डीजल है वहां एंबुलेंस, स्कूल बस, नगर निगम के वाहनों में पर्याप्त पेट्रोल-डीजल दिया जा रहा है जबकि अन्य वाहनों को कम दिया जा रहा है। बाइक के लिए 1 लीटर निर्धारित कर दिया गया है। बिलासपुर जिला प्रशासन ने सोमवार को स्थानीय ट्रक-बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक ली। ड्राइवरों को हड़ताल पर नहीं जाने की समझाइश दी गई। ट्रक और बस मालिकों से कहा गया कि वे अपने ड्राइवरों को टोल प्लाजा में अनावश्यक रूप से ट्रक खड़ा करने से मना करें।

बाबू भैया की कलम से

सौम्य-सरल साय पर 'सिस्टम' और 'मुफ्त' का बोझ

प्रदेश के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीधे व सरल व्यक्ति हैं। समाज में इसे व्यक्ति का गुण माना जाता है। जिसकी प्रंशसा होती है और होनी भी चाहिए। अब समाज की बेहतरी के लिए ,जनविकास के लिए श्री साय प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासानिक पद पर विराजमान हुए हैं। यहां उनका सीधापन ,सौम्यता,सरलता आम जनों को तो सुहाएगी, इसमें किसी को शक -ओ-सुबहा कतई नहीं है। प्रशासन चलाने के लिए तो इन गुणों के साथ सिस्टम को साधने व उनसे काम लेने के लिए समझ व कड़ाई की जरूरत पड़ेगी। समझ में तो कहीं कोई कमी नहीं लगती है। लंबे राजनीतिक पदों पर रहते हुए उन्होंने निश्चित रूप से उनमें परिपक्वता हासिल कर ली होगी। सरल व्यक्ति एकदम से कड़ाई करने का मन नहीं रखता। प्रशासन के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। सबसे बड़ा खतरा प्रशासनिक अधिकारियों से होता है जो सरलता का फायदा उठाने के माहिर खिलाड़ी होते हैं। यह अनेक मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में देखा गया है कि सीधेपन व सरलता का गलत फायदा सिस्टम में बैठे लोग उठाने लगते हैं। आरोप लगते हैं कि सत्ता तो अधिकारी चला रहे हैं। ऐसे माहौल के बनने पर हमने सत्ता को बदलते देखा है। जब सौम्य ,सरल व व्यवहारिक व्यक्तित्व के धनी होने के बावजूद सत्ता से बेदखल होना पड़ा है। सरलता का लाभ उठाने वाले सिर्फ सिस्टम के लोग ही नहीं अपने लोग भी होते हैं, जो धीरे धीरे जकड़ना शुरू करते हैं। आरोप लगते हैं कि मुख्यमंत्री को घेर लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से छतीसगढ़ की जनता को बड़ी आस है। यह आस जगी ही लोक लुभावन वायदों के कारण है। छतीसगढ़ में महतारी वंदन योजना में प्रति विवाहित महिला को 1000 प्रतिमाह यानी 12000 प्रति वर्ष देना,3100 प्रति क्विंटल ,प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी,एकमुश्त भुगतान, 18 लाख गरीबों के अटके आवास बनाकर पात्र को सौंपना, दो साल का बकाया बोनस देने के वायदे प्रमुख माने गए हैं। वैसे 'मोदी की गारंटी' के वायदे तो कुल जमा 20 हैं, परंतु अभी हाल इन चार पर लोगों की निगाह जमी हुई है। मुख्यमंत्री चाहते भी यही हैं कि ये वायदे जल्द व समय सीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई है। बकाया बोनस खातों में भेजा जा चुका है। सरकार अपना काम कर रही है तो सिस्टम भी अपना काम कर रहा है। अनेक स्थानों में सहकारी बैंकों की शिकायत पात्र किसान कर रहे हैं। कुछ पात्र लोग नाम काटे जाने की जानकारी भी दे रहे हैं। राजकोष के हालात भी स्वस्थ नहीं हैं। राशि जुटानी है। मजबूत वित्त मंत्री हैं। एक आशा की किरण डबल इंजिन की सरकार का कॉन्सेप्ट भी है। बड़ा कर्ज लेने की मजबूरी भी सामने होगी। पहले ही 86000 करोड़ के कर्ज से छतीसगढ़ जूझ रहा है। प्रति माह ब्याज में भारी रकम टूट रही है। एक अखबार की रिपोर्ट पर भरोसा करें तो कर्नाटक,राजस्थान,तेलंगाना,व छतीसगढ़ कर्ज की राशि उठाने वालों में टॉप 10 में शामिल हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने सम्पूर्ण भारत के राज्यों पर जारी एक रिपोर्ट में कहा है कि जनवरी-मार्च तिमाही में देश के राज्य 4.13 लाख करोड़ का कर्ज बाजार से लेगें। 2023-24 में अप्रैल से अक्टूबर तक 7 महीने में कुल 2.58 लाख करोड़ बाजार से उठाए थे। अर्थ यह कि अगले तीन माह में 7 माह की तुलना में 60त्न अधिक कर्ज लेंगें। इस रिपोर्ट के अनुसार हालांकि छतीसगढ़ में 2022-23 में सरकार ने कोई भी कर्ज नहीं लिया था,बल्कि पिछले कर्ज में से 2.227 हजार करोड़ कर्ज चुकाया था। इस वर्ष जनवरी से मार्च 24 में 11 हजार करोड़ का कर्ज लेने का अनुमान बताया गया है। इस तरह कर्ज बढ़कर लगभग एक लाख करोड़ प्रदेश के सर पर हो जाने का अनुमान है। यह भी बताया गया है कि राज्यों के लोक लुभावने वायदों को पूरा करने व योजनाओं को लागू करने के लिए धन जुटाने कर्ज के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं होता है। छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सामने भी मुफ्त की योजनाओं को पूरा करने की चुनौती मौजूद है। यह भी सोचना है कि प्रदेश की जनता के सर पर कर्ज का अधिक बोझ ना पड़े। मितव्यविता पर भी फोकस करना है। प्रयास शुरू भी कर दिए गये हैं। अनावश्यक खर्च से बचने की सलाह दी गई है। बगैर सरकार की नजर में लाये खर्च ना करने के निर्देश भी हैं। सौम्य सरल मुख्यमंत्री की इस सलाह को सिस्टम कितनी गंभीरता से लेता है, यह देखने वाली बात होगी। यह साफ झलक रहा है कि सरकार के वायदे तो पूरे हो जाएंगे। 'मोदी की गारंटी' भी पूरी कर दी जाएगी। राजनैतिक रूप से सरकार को प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी। उसकी कीमत इन वायदों से लाभान्वित जनता को अपने ही ऊपर लदे कर्ज से चुकानी पड़ेगी। यानी हाथ घुमा कर कान पकड़ने वाली बात हुई। जेब में पैसा आएगा और सर पर कर्ज चढ़ेगा, यानी लिया दिया सब बराबर। संकेत साफ है कि जनता को मुफ्त की आदत छोड़नी पड़ेगी अन्यथा आने वाली पीढियां इस कर्ज के बोझ तले अपने को दबा महसूस करेंगीं।

नगर निगम जोन 7 ने लगभग 2000 वर्गफीट पर निर्मित व्यावसायिक निर्माण तोड़ा

■ **जोन 2 द्वारा महालक्ष्मी मार्केट में अवैध निर्माण को हटाया गया**

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर में जोन क्र. 7 के आने वाले तात्यापारा वार्ड क्र. 37 के अंतर्गत रामसागरपारा, बम्लेश्वरी मंदिर के पास ममता लखवानी द्वारा नगर निगम से अनुमति के विपरीत लगभग 2000 वर्गफीट पर व्यावसायिक निर्माण कराया गया था, जिसे नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धाराओं के तहत प्रथम नोटिस धारा 293 (1) (11) व 302, द्वितीय नोटिस धारा 307 (2) (अ) एवं अंतिम तृतीय नोटिस धारा 307 (3) नियमानुसार नोटिस जारी कर

कार्यवाही करते हुए आज पुलिस बल एवं नगर निगम के टीम के साथ संयुक्त रूप से अवैध निर्माण को तोडऩे की कार्यवाही की गई। कार्यवाही में भवन के द्वितीय तल के स्लैब को तोड़ा गया।

इसके साथ ही निर्माणकर्ता द्वारा उक्त भवन का राजीनामा कराये जाने हेतु समस्त दस्तावेज के साथ आवेदन प्रस्तुत करने हेतु 3 दिवस का समय मॉगते हुए तत्काल लिखित में जवाब इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। अतएव वर्तमान में उक्त कार्यवाही को स्थगित किया गया है।

जोन 6 नगर निवेष विभाग द्वारा आज जोन के तहत चंद्रषेखर आजाद वार्ड क्रमांक 60 के गोकूल नगर क्षेत्र के मुख्य मार्ग में नाले के ऊपर अभियान चलाकर अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई है। जोन की टीम ने जोन के ब्रिज नगर क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के प्रकरण पर अभियान चलाकर कार्यवाही की है। जोन 1 के क्षेत्र में नगर निवेष विभाग की टीम ने बिना अनुमति निर्माण के प्रकरण में अभियान चलाकर कार्यवाही की है।

नगर निवेष विभाग द्वारा आज अभियानपूर्वक कार्यवाही के तहत जोन 4 नगर निवेष विभाग की टीम ने जोन क्षेत्र में हिन्दू हाई स्कूल के पास अभियान चलाकर ठेले की जप्ती की कार्यवाही की । सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाया गया। गोल चैक के पास चूना मार्किंग की कार्यवाही की गई। जोन 3 द्वारा बलौदाबाजार मेन रोड में अभियान चलाया गया। लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 34 के तहत मरीन ड्राइव तेलीबांधा में 5 ठेले हटाकर जप्त किये गये एवं शंकरनगर वार्ड क्रमांक 30 में बीटीआई के सामने और महात्मा गांधी वार्ड क्रमांक 12 में लोधी पारा चैक के पास अस्थायी ठेले को हटाकर सामग्री जप्त की गई। जोन 4 द्वारा कालीबाडी मुख्य मार्ग में अभियान चलाया गया।

अचानक स्थगित हुई केबिनेट की बैठक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक अचानक टाल दी गई है। बताया जाता है कि राज्य के पांच मंत्रियों को अचानक जयपुर-राजस्थान बुलाया गया है। जयपुर में भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। यह बैठक क्यों और किस विषय को लेकर होगी? इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से वरिष्ठतम मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, डिप्टी सीएम अरूण साव, विजय शर्मा, केदार कश्यप के साथ एक और मंत्री जा रहे हैं। ये सभी चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं। इस बैठक की वजह से आज की कैबिनेट कल तक स्थगित कर गई है। पहले जयपुर बैठक भी कल होनी थी जिसे प्रोस्पोन किया गया है। बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि इस पर रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राज्यवार कार्यक्रम बनाया जा रहा है। वैसे एक अनाधिकृत खबर यह भी बताई गई है कि प्रदेश के संगठन प्रभारी ओम माथुर की आज 75वीं वर्ष गांठ हैं। इस मौके पर जयपुर में अमृत महोत्सव का आयोजन है जिसमें शामिल होने तीन मंत्री साव, अग्रवाल, शर्मा जा रहे हैं। केदार कश्यप जयपुर पहुंच चुके हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

गरीबों के जीवन में खुशहाली लाना ही रामराज्य है-बृजमोहन

रायपुर। पहले समय में जब संयुक्त परिवार होते थे तब बड़े बुजुर्गों के जरिए बच्चों को सनातन

धर्म के बारे में जानकारी मिलती रहती थी,लेकिन अब एकल परिवार के कारण मां-बाप के पास इतना समय ही नहीं होता है कि अपने बच्चों में सनातन धर्म संस्कृति, संस्कार और ज्ञान की जानकारी दे सकें। ऐसे में श्रीमद् भागवत कथा, श्रीराम कथा और श्रीशिव पुराण कथा का आयोजन करके सनातन धर्म को आगे ले जाया जा सकता है। ये संदेश धर्मस्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने श्रीराम कथा ज्ञान महायज्ञ के दौरान कही। मंत्री अग्रवाल त्रिमूर्ति मंदिर मठपुरैना में श्रीराम कथा ज्ञान महायज्ञ में शामिल हुए उन्होंने कथा वाचक साध्वी स्मिता दीदी का सम्मानित कर आशीर्वाद लिया। मंत्री अग्रवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि, तकलीफें सभी के जीवन में आती हैं लेकिन उनसे परेशान होने और डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु श्रीराम ने भी 14 साल वनवास में गुजारे। इस दौरान बहुत सी तकलीफें का सामना किया। लेकिन जब वापस अयोध्या लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाकर लौटे। उन्होंने कहा यह हिंदू जागरण का समय चल रहा है। अयोध्या में जन्म स्थान पर प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर लगभग तैयार हो चुका है। काशी विश्वनाथ और महाकाल में भी कॉरिडोर बन गए हैं। जो हिंदू जागरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि, जब हम परेशान होते है तब भगवान को याद करते हैं।

भारी भरकम जुर्माना और लंबी सजा का प्रावधान वाहन चालकों के प्रति अन्याय है - मलकीत

रायपुर। केंद्र की मोदी सरकार के काले

कानून के खिलाफ ड्राइवरों द्वारा देश भर में हो रहे हड़ताल का समर्थन करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने कहा है कि निजी बीमा कंपनियों को मुनाफा पहुंचने के लिए यह जन विरोधी नीति थोपी गई है। वाहन चालक आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं होते हैं, की 7 लाख रुपए का जुर्माना पटा सके। गरीब ड्राइवरों पर दोहरी मार केंद्र की मोदी सरकार के फैसले से पड़ने वाली है, एक तरफ भारी भरकम जुर्माना, दूसरी तरफ 10 साल जेल की सजा ऐसे में जब परिवार का कमाने वाला मुखिया एक ड्राइवर 10 साल के लिए जेल चला जाएगा तो उसके परिजनों का क्या होगा? उनका भरण पोषण कैसे होगा? केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा थोपे गए इस काले कानून से देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वाहन चालक वर्ग बुरी तरह से भयभीत है। दुर्घटना जानबूझकर नहीं होते नहीं होते, ऐसे में भारी भरकम जुर्माना और लंबी सजा का प्रावधान आम वाहल चालकों के सामर्थ्य से बाहर हैं, अमानवीय है, अव्यावहारिक है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने कहा है कि मोदी सरकार के जन विरोधी नीतियों पर परदेदारी करने भाजपा के नेता कुतर्क कर रहे हैं कि अधिक जुर्माना राशि से दुर्घटनाओं में पीड़ितों को

प्रदेश के 72 लाख़ परिवारों को मिल रहा है खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का लाभ

रायपुर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी

जायसवाल के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि राज्य के पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार की जनकल्याण जानकारी योजना 'डॉ. खूबचंद बघेल मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना' का लाभ छत्तीसगढ़ के सभी 72 लाख परिवारों को मिल रहा है, अचानक बंद करने से इस योजना से इलाज के अभाव में मध्यवर्ती लोग बे-मौत मरेंगे। ऐसी योजना को बंद करना छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के प्रति बेईमानी होगी। आयुष्मान योजना के तहत दी जाने वाली 10 लाख रुपए तक की इलाज सुविधा केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए ही है। यह भी सर्वविदित है कि भाजपा नेताओं के संरक्षण में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता रहा है। मध्य प्रदेश सहित कई भाजपा शासित राज्यों में मृत व्यक्तियों के इलाज के नाम पर करोड़ों की राशि आयुष्मान योजना से निकाल ली गई जिसका खुलासा विगत दिनों सीएजी के रिपोर्ट में हुआ है। एक ही मोबाइल नंबर से लाखों हितग्राहियों के आयुष्मान योजना में पंजीयन का खुलासा भी विगत दिनों हुआ है, जिसमें वह मोबाइल नंबर भी फर्जी पाया गया। राज्य सरकार द्वारा गरीब और मध्यम वर्ग के चिकित्सा सहायता की महत्वपूर्ण योजना को बंद करके केवल गरीब वर्ग के लिए इलाज का प्रावधान नाकाफी है।

मोदी सरकार की स्पष्ट नीति पेट्रोल डीजल में मुनाफाखोरी करो और जनता पर महंगाई लादो-धनंजय

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता

धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि मोदी सरकार की स्पष्ट नीति है पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाकर मुनाफाखोरी करो और पेट्रोलियम कंपनियों को मुनाफाखोरी करने दो और जनता महंगाई के बोझ तले दबे रहे। बीते तीन माह में अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के कीमतों में लगभग 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है लेकिन राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल एवं डीजल के कीमतों में किसी प्रकार से संशोधन नहीं किया गया है. जनता पर मोदी निर्मित महंगाई दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का फर्क किचन से लेकर खेत खलिहान तक, स्कूल से लेकर कॉलेज तक और फैक्ट्री तक दिखता है। हर आवश्यक वस्तुओं के दामों में तेजी होता, लेकिन आम लोगों के आय में किसी प्रकार से कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। शासकीय कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने केंद्र सरकार महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी कर देती है इससे कुछ राहत कर्मचारियों को मिलता है लेकिन आम जनता, किसान, युवा, व्यापारी, महिलाए, मजदूर, रेहड़ी खोमचा वालों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार कोई पॉलिसी नहीं बनाती है बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार आम जनता की जेब से पेट्रोल डीजल की मुनाफाखोरी करके 35 लाख करोड़ से अधिक की राशि निकाल चुकी है और आज भी जनता को निचोड़ रही है।

धान खरीदी की तिथि दो महीने बढाई जाय -सुशील आनंद

रायपुर। कांग्रेस ने मांग किया है कि धान

खरीदी की तिथि दो महीने बढाई जाय। कांग्रेस संचार विभाग के़ अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि इस वर्ष के़ लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 135 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया था, तब प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर से खरीदी होना था, वर्तमान में ज़ब प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदी के़ आदेश जारी हो गए है तो लक्ष्य भी बढ़ेगा कम से कम 150 लाख मिट्रिक टन खरीदी पहुंचेगी। अभी तक दो महीनो मे बमुश्किल 65 लाख मिट्रिक टन खरीदी हुयी है। सरकार ने केवल एक महीने की तिथि बढ़ाई है जो अपर्याप्त है। पूरे लक्ष्य कि प्राप्ति हेतु तथा सभी किसान अपना धान बेच सके इसके लिए जरूरी है कि धान खरीदी कम से कम दो महीने बढाई जाय। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि किसान धान खरीदी केन्द्रों में अपना धान बेचने पहुंच रहे है लेकिन किसानों में दुविधा की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानो से वादा किया है कि वह धान की क़ीमत 3100 रु. प्रति क्विंटल देगी तथा इसका एक मुश्त भुगतान धान बेचने के़ तुरंत बाद खरीदी केन्द्रों की ग्राम पंचायतों में ही अलग से काउंटर बना कर किया जायेगा। इस संबंध में शासन के़ तरफ से कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है और न ही कोई निर्देश जारी हुआ है, जिसके कारण उनको समर्थन मूल्य पर ही भुगतान हो रहा है।

खेल मंत्री ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश

खेल अकादमियों को साधन संपन्न और खेल प्रशिक्षण ढ़ांचे को मजबूत बनाने की जरूरत : टंकराम

रायपुर। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने आज यहां न्यू सर्किट हाऊस में विभागीय अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात के दौरान प्रदेश की खेल अकादमियों को साधन सम्पन्न और खेल प्रशिक्षण ढ़ांचे को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान खेल मंत्री ने उनसे विभागीय गतिविधियों की विस्तार से जानकारी ली। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री नीलम नामदेव एक्का, संचालक श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा सहित खेल संचालनालय के अधिकारीगण इस मौके पर उपस्थित थे।

खेल सचिव एक्का एवं खेल संचालक श्रीमती सिन्हा ने प्रदेश में संचालित सभी आवासीय खेल अकादमियों एवं गैर आवासीय खेल अकादमियों, विभिन्न खेल गतिविधियों सहित युवा कल्याण गतिविधियों की जानकारी उन्हें दी। खेल मंत्री ने कहा कि वर्तमान में संचालित खेल अकादमियों को साधन संपन्न बनाने और खेल प्रशिक्षण के ढ़ांचे को और अधिक मजबूत बनाने तथा प्रशिक्षण गतिविधियों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने की जरुरत है। नई तकनीकों के साथ विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए। उन्होंने विभागीय योजनाओं के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट की जानकारी भी अधिकारियों से ली। प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

खेल मंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध खेल मैदानों और वहां उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में बच्चों को खेलने के लिए सुव्यवस्थित खेल मैदान उपलब्ध कराने के लिए खेल मैदानों को विकसित करने की कार्यवाही की जाए। सभी जिलों के सभी गांवों में खेल मैदान हेतु उपयुक्त भूमि को चिन्हित कर खेल मैदान बनाने हेतु सुरक्षित करने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए।

खेल मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि राजीव युवा मितान क्लब योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राशि अंतरण और राशि के व्यय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को जारी किया जा चुका हैं, जिसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

खेल मंत्री ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों के कौशल का समुचित विकास सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने एवं विभागीय योजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।

सेंट्रल जीएसटी की टीम ने बोरियाकला में मारा छापा, संचालक के घर मिला 2.88 करोड़ कैश

■ **पैकेजिंग फैक्ट्री से 2.66 करोड़ का स्टॉक जब्त**

रायपुर। केन्द्रीय जीएसटी की टीम ने राजधानी रायपुर के बोरियाकला क्षेत्र में संचालित एक पैकेजिंग फैक्ट्री में छापा मारकर 2.66 करोड़ का स्टॉक जब्त किया। फैक्ट्री मालिक के घर की तलाशी लेने पर 2.88 करोड़ रुपए कैश भी मिला। अफ्सरों को इनपुट मिला था कि रायपुर में कई जगहों पर तंबाकू और गुटखा की अवैध फैक्ट्री चल रही है। इनमें करोड़ों के टैक्स की हेराफेरी की जा रही है। गुटखे की पैकेजिंग का काम भी शहर के कई जगहों पर हो रहा है।

सेंट्रल जीएसटी के अफ्सरों को पुख्ता जानकारी मिलने के बाद विभाग की टीम ने धमतरी रोड पर स्थित मेसर्स ओम रोटो प्रिंटर्स बोरियाकला में छापा मारा। बाहर से देखने पर यह सामान्य प्रिटिंग प्रेस जैसा दिखाई देता है मगर यहां अंदर फैक्ट्री में तंबाकू, पान मसाला ब्रांड के लिए पैकेजिंग बनाई जा रही थी।

अधिकारियों ने फिल्म, फॉइल, स्ट्रिप्स, प्लास्टिक का कच्चा माल जब्त किया है। यहां पैकेजिंग का निर्माण और सप्लाई पूरी तरह से गुप्त तरीके से किया जा रहा था। जिसकी खबर आसपास के लोगों को भी नहीं थी। गुटखे की पैकेजिंग के रैपर को प्रिंट कर दूसरे राज्यों में भी भेजा जा रहा था।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.